

» कृषि

» विश्लेषण

» जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

मार्गशीर्ष-पौष 2076, दिसंबर 2019

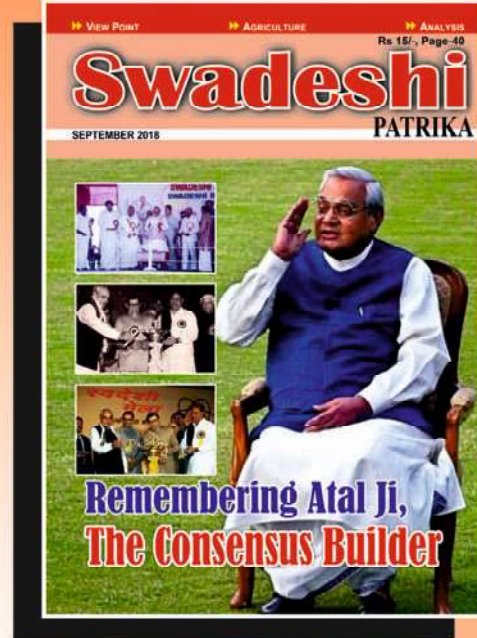
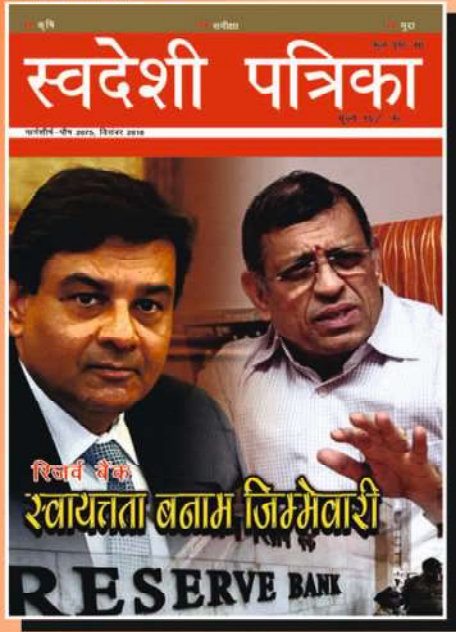


14वीं राष्ट्रीय सभा
हoshangabad (उत्तराखण्ड)

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

स्वदेशी पत्रिका



SWADESHI Patrika

वार्षिक सदस्यता (Annual Subscription) :

150/-

आजीवन सदस्यता (Life Membership) :

1500/-

*For subscription please send payment by A/c payee
Cheque/Demand Draft/Money Order
in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in*

**Bank of India, A/c No. 602510110002740,
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)**

*Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately
or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)***

पढ़ें और पढ़ायें

आवरण कथा - पृष्ठ-6

14वीं राष्ट्रीय सभा हरद्वार (उत्तराखंड)



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

16 साक्षात्कार

‘घाटे में न बिके, एयर इंडिया-बीपीसीएल’: डॉ. अश्वनी महाजन

19 आजकल

सब काम रोबोट से होगा, तो इंसान क्या करेगा?

..... अनिल तिवारी

21 विचार

मंदी से उबरने का एक नुस्खा यह भी

..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

23 मुद्दा

बेल्ट रोड के रास्ते विस्तारवाद को अंजाम देता चीन

..... स्वदेशी संवाद

25 बहस

आर्थिक सुस्ती है, मंदी नहीं

..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

28 जल प्रबंधन

गंगा को चाहिए एक और भगीरथ

..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

30 विश्लेषण

तकनीकी-व्यवसायिक सहजीविता और भारत का आर्थिक विकास

..... के.के. श्रीवास्तव

33 संसद से

देर आए दुरुस्त आए : नागरिकता संशोधन बिल पारित

वर्ष-27, अंक-12
मार्गशीर्ष-पौष 2076 दिसंबर 2019

संपादक

अजेय भारती

सह-संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर
दास महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेंट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-38



तृतीय मुख्य पृष्ठ

39

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ

40



पाठकनामा

एक शिक्षक के हजार काम

केंद्र तथा राज्य की सरकारें शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावें करती रही है। किसी भी देश का न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य भी शिक्षा के रास्ते ही आगे बढ़ता है। शिक्षा हमारे देश में प्राचीन काल से ही पोषित रही है। रघुवंश में वर्णन आता है कि महाराज रघु ने अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आये शिष्य से पूछा था कि गुरु का स्वास्थ्य कैसा है, गुरुकुल का पर्यावरण कैसा है, पेड़ों और नदियों को आंधी तूफान से कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है।

आज स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। छोटी-छोटी बातों के लिए शिक्षकों को न सिर्फ हड़ताल करना पड़ रहा है बल्कि देश के कई हिस्सों में उन्हें लाठियां भी खानी पड़ रही है। पहले के राजा-महाराजा की तरह लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकारें शिक्षा में निवेश करती थी। उदारीकरण के बाद तस्वीर बदल गई है। अब सरकारें शिक्षा पर खर्च करती है। न सिर्फ खर्च करती है बल्कि अपने बजट में उस खर्च का ढिंढौरा भी पीटती है। कोई भी व्यक्ति किसी छोटे काम में भी छोटा भी निवेश करता है तो उसे एक फल की आशा रहती है और समय के साथ उसको निवेश का लाभ मिलता भी है। लेकिन खर्च तो हमेशा जाया होता है। लगता है कि इसीलिए शिक्षा की दुरगति हो रही है, क्योंकि अब निवेश नहीं, खर्च हो रहा है। खर्च करने के कारण ही सरकारें भी शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा वह सब काम करवा रही है जो शायद नहीं कराना चाहिए। मसलन— टीके लगवाना, वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव में ड्यूटी करना, स्वच्छता अभियान में मदद करना, चकबंदी में हाथ बटाना, पेयजल का सर्वे करना, पानी का सैंपल जांच करवाना, जैसे हजारों काम सरकारें शिक्षकों से ले रही है। यह न सिर्फ शिक्षा पद्धति का मजाक है बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेपढ़ बनाये रखने की सुनियोजित साजिश भी।

संजय कुमार (बवाना, दिल्ली)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क ‘स्वदेशी पत्रिका’ दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

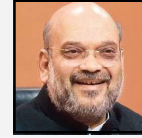
यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएँ विविधता में एकता के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाती हैं।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)



लोकतंत्र में कानून सभी के लिए समान है, एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं है। हम परिवार का विरोध नहीं करते हैं। हम परिवारवाद का विरोध करते हैं।

अमित शाह (गृहमंत्री, भारत)



भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने महसूस किया है कि जब भी ह्यूमन पीस क्राइसिस का खतरा हुआ है या ग्लोबल पीस एंड स्टैबिलिटी के लिए खतरा है, भारतीय सेना ने जो व्यावसायिकता पेश की है, वह बेजोड़ है।

राजनाथ सिंह (रक्षामंत्री, भारत)



स्वदेशी को अपनाने से देश का गौरव बढ़ता है। स्वदेशी उत्पाद और विचार आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं।

बेबी रानी मोरिया (राज्यपाल, उत्तराखंड)

ग्लोबल स्वदेशी

आज से तीन दशक पहले आकार में आया वैश्वीकरण पिछले लगभग चार वर्षों में 'रिवर्स गियर' में चला गया है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, जो बाद में यूरोप में ब्रेक्सिट द्वारा प्रकट हुआ। पिछले दो वर्षों में, भारत ने भी घरेलू उद्योग की रक्षा करने के उद्देश्य से विदेशों से आयात को रोकने के लिए अधिक आक्रामक तरीके से टैरिफ बढ़ाने और एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू करना शुरू कर दिया है। 1990 के बाद से ही दुनिया भर में व्यापार और शुल्क, गैर-टैरिफ दोनों के लिए सभी बाधाओं को दूर करते हुए व्यापार को मुक्त करने की प्रवृत्ति रही है। विश्व व्यापार संगठन, या विश्व व्यापार संगठन के संविधान के अनुसार, यदि कोई भी देश व्यापार के लिए बाधाएं लगाता है, तो प्रभावित देश विवाद निपटान तंत्र का उपयोग कर सकता है।

हाल तक, कोई भी देश संरक्षणवाद की स्पष्ट रूप से पैरवी नहीं कर रहा था, बल्कि पहले से की गई बाधाओं को हटाया जा रहा था। भारत में, विश्व व्यापार संगठन से पहले 400 प्रतिशत से अधिक का आयात शुल्क कई वस्तुओं पर लगाया जाता था और 1400 से अधिक वस्तुएं थीं, जिन पर मात्रात्मक नियंत्रण (क्यूआर) लगाए गए थे। इसके विपरीत, आज कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो 0-10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जाता है, और क्यूआर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पिछले 15 वर्षों में चीन द्वारा आक्रामक व्यापार की वजह से दुनिया भर के बाजारों को उसके उत्पादों द्वारा आच्छादित किया गया है। इस प्रक्रिया में दुनिया भर के अधिकांश उद्योग बंद होने लगे। चीन एक विनिर्माण केंद्र में बदल गया और चीन के साथ अधिकांश देशों का व्यापार घाटा बढ़ने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने चुनाव अभियान में अमेरिकी उद्योगों के बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने जंग खा रही अमेरिकी फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करने, रोजगार सृजित करने और आयात पर भी रोक लगाने का वादा किया।

भारत में, यह एक खुला रहस्य है कि चीनी उत्पादों के बड़े पैमाने पर डंपिंग के कारण, हमारे अधिकांश सहायक उद्योग बंद हो गए। हमारे अधिकांश छोटे उद्योग ऑटोमोबाइल, दवा, रसायन और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे बड़े उद्योगों के सहायक हैं। परिणामस्वरूप, जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा या तो स्थिर हो गया या कुछ वर्षों में घट गया। यह सभी जानते हैं कि हमारा घरेलू उद्योग सस्ते चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम उद्योगों के साथ-साथ हमारी स्थापित मशीनरी, रासायनिक और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए।

इसके बावजूद, टैरिफ या यहां तक कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लागू करके चीनी हमले से उद्योग की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। चीन एक घोषित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। भारत में मुक्त व्यापार के सिद्धांत में नीति निर्माताओं और मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों का अत्यधिक विश्वास था। यह विश्वास इतना गहरा था कि विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में लचीलेपन का उपयोग करने के लिए उनके द्वारा हर तरह का प्रयास किया गया था। इन समझौतों में प्रत्येक देश ने प्रत्येक वस्तु के लिए शुल्क की एक बाध्य दर तय है। जबकि, मुक्त व्यापार में विश्वास के कारण, हमारी लागू टैरिफ दरें बाध्य दरों की तुलना में बहुत कम हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास औसत 40 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए लचीलापन है (जिसे हम बाध्य टैरिफ कहते हैं)। इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बाधाओं को बढ़ा सकता है। मुक्त व्यापार के सिद्धांत में अत्यधिक विश्वास के कारण, अब तक हमने इन उपायों का अधिक उपयोग नहीं किया है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि नीति निर्माता व्यापार असंतुलन के बावजूद जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

आमतौर पर देश खेल के नियमों का पालन करते रहे हैं। हालांकि, हाल के दिनों में मुक्त व्यापार के खिलाफ आवाजें अधिक स्पष्ट हो गई हैं। सबसे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष रूप से चीन से आयात के मुक्त प्रवाह के खिलाफ कई टिप्पणियां कीं। अधिकांश वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाने के उनके निर्णय ने एक बहस को जन्म दिया है कि क्या दुनिया संरक्षणवाद के रास्ते पर जाएगी। विश्व आर्थिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संरक्षणवाद आतंकवाद से कम विनाशकारी नहीं है। लेकिन, इसके तुरंत बाद, जब बजट में विभिन्न वस्तुओं पर सुरक्षात्मक टैरिफ लगाया गया था, तो मुक्त व्यापार के नायक इसे पचा नहीं पा रहे थे।

संरक्षणवाद बुरा नहीं होता है। यह सही है कि मुक्त व्यापार अगर ईमानदारी से अपनाया जाए, तो फायदे का सौदा है। लेकिन हम पाते हैं कि देश ईमानदारी से मुक्त व्यापार को नहीं अपना रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि चीन और अन्य देशों द्वारा माल डंप करने के कारण हमारा उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सका और इसे बंद करना पड़ा। यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का पालन करते हुए और उसमें उपलब्ध लचीलेपन का उपयोग करते हुए, घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने में सक्षम है, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह अतीत का संरक्षणवाद नहीं है। यह मुक्त व्यापार के भयानक अनुभव पर आधारित एक नया 'सूचित संरक्षणवाद' है। यह राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, न कि मुक्त व्यापार के कट्टरपंथियों के कट्टरपंथी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे हम 'ग्लोबल स्वदेशी' कह सकते हैं।



14वीं राष्ट्रीय सभा

29, 30 नवंबर व 1 दिसंबर 2019

हरद्वार (उत्तराखंड)

उद्घाटन समारोह: स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा प्रातः 10.15 पर आचार्य श्री बालकृष्ण जी के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुई। इसके साक्षी बने श्री रूपेंद्र सिंह जी सोढी (निदेशक अमूल इंडिया गुजरात) तथा श्री रूप किशोर शास्त्री (उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार)

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री अरुण ओझा, संगठक श्री कश्मीरी लाल, सह संयोजकगण डॉ. अश्वनी महाजन, श्री धनपतराम अग्रवाल, श्री आर सुंदरम, श्री अजय पत्की, अ.भा. महिला प्रमुख श्रीमती अमिता पत्की तथा विविध क्षेत्र के श्री पवन कुमार (भा.म. संघ), श्री लक्ष्मी नारायण भाला सहित कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्री विनोद चौधरी, श्री रमाकांत भारद्वाज तथा संत श्री रूपेंद्र स्वामी जी मंच को सुशोभित कर रहे थे।

मंच पर विराजमान अतिथियों का परिचय व संचालन डॉ. राजीव कुमार (क्षेत्र संयोजक उ.प्र.) ने किया।

आचार्य बालकृष्ण ने उद्बोधन का प्रारंभ भारत माता की जय से किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व कल्याणकारी है, वहीं पश्चिम के लोग भारत को बाजार

मानते हैं इस बाजारवाद से लड़ाई का नाम है स्वदेशी। हम स्वदेशी संस्कृति के उपासक हैं। भारत का निर्माण भारत से होगा, इंडिया से नहीं। भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति— वह स्थानीय उद्यमी (आर्टिसेन) हो या अन्य कार्य करने वाला, भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा रहता है। देश में वर्तमान में 7 करोड़ से अधिक आर्टिसेन जो भारत की माटी से जुड़े हुए हैं और छोटे-छोटे उत्पाद बना रहे हैं। विदेशी कंपनियां इन उद्यमों को समाप्त करना चाहती हैं। विदेशी कंपनियां अपने विज्ञापन के माध्यम से एक धारणा बना चुकी है कि विदेशी वस्तुएं ही श्रेष्ठ हैं जबकि ऐसा नहीं है।

आज देश में आयुर्वेद के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है। सैकड़ों कंपनियां आंवला, एलोवेरा जैसे प्राकृतिक पेय का निर्माण कर रही हैं। यह स्वदेशी की जीत है।

श्री रूपेंद्र सोढी (एमडी अमूल) ने 73 वर्षों के अमूल का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमूल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी बन गई है। अमूल व स्वदेशी के कारण देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर एक बन गया है। उन्होंने कहा विदेशी कंपनियां भारत में चैरिटी के लिए नहीं आती, अपितु वह पैसा कमाने आती हैं। भारत में

प्रस्ताव-1

जैविक-प्राकृतिक-परंपरागत कृषि ही है लाभकारी

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा ने भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति और किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्बल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत की आत्मा अपने गांवों में निहित है। प्राचीन भारतीय गाँव आत्मनिर्भर थे, जिनमें कुशल समुदाय शामिल थे और सभी लोग आत्मनिर्भर थे। देश के भोजन का उत्पादन करने के अलावा उन्होंने शहरों को प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों की आपूर्ति की। शहर, गांवों पर निर्भर थे और दुनिया भर में व्यापार और निर्यात किए जाने वाले इन सामानों और उत्पादों के प्राथमिक आपूर्ति के केंद्र थे, गांव। इसके परिणामस्वरूप भारत 'सोने की चिड़िया' कहलाया और दुनिया के कुल उत्पाद (जीडीपी) का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत का हो गया। दुर्भाग्य से, आज के गांव पूरी तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे शहरों पर निर्भर हो गए हैं।

भारत में हरित क्रांति ने उच्च उपज देने वाली किस्मों, बीजों, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को अपनाने और मशीनीकरण के कारण पारंपरिक कृषि को एक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया। हालांकि इसने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की और भारत को एक खाद्य अधिशेष राज्य बना दिया, लेकिन किसानों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक और वित्तीय समस्याएं पैदा कर दी। फसलों के लागत मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई। पर नतीजा यह हुआ कि कृषि पर निर्भरता 1947 में 70 प्रतिशत से 44.8 प्रतिशत तक कम हो गई है, साथ ही साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 49 से 14 प्रतिशत तक कम हो गया है। किसानों को संस्थागत फसल ऋण अब 11.68 लाख करोड़ रुपये है। इस तरह के भारी इनपुट लगाने के बाद भी, कृषि उत्पादकता में स्थिरता आई है और कृषि क्षेत्र की वृद्धि आम तौर पर स्वीकृत 4 प्रतिशत के स्तर से भी कम 2.8 प्रतिशत है। आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण आय में असमानताएं हुई, जिससे संकट और बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं करने लगे। एमएसपी वृद्धि ने आम तौर पर संपन्न किसानों को लाभान्वित किया और भंडारण एजेंसियों के साथ 50 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न की अभूतपूर्व मात्रा में वृद्धि की, परंतु इससे सब्सिडी का बोझ कई गुना बढ़ गया।

रासायनिक खेती ने हमारी मिट्टी, पानी, नदियों, हवा, भोजन और यहां तक कि मां के दूध में भी जहर घोल दिया है। कैंसर, हार्टअटैक, डायबिटीज, बीपी, मनोवैज्ञानिक विकार इत्यादि के खतरे वाले जीवन अब सामान्य हैं। कॉटन बेल्ट में 'कैंसर ट्रेन' रासायनिक खेती का उपहार है। महंगे कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग ने न केवल खेती की लाभप्रदता को कम किया है, बल्कि राष्ट्र के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे भी पैदा किए हैं।

उत्पादन की बढ़ती लागत ने 25 प्रतिशत छोटे किसानों को खेती से बाहर कर दिया और 31 प्रतिशत सीमांत किसान उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। रासायनिक खेती ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया, बल्कि गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन के कारण रोजगार में कमी आई है। अकेले दस वर्षों में, शहरी आबादी 25.6 प्रतिशत से बढ़कर 30.2 प्रतिशत हो गई है।

भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने इन दुष्परिणामों को स्वीकार किया और अनेक वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि पारंपरिक कृषि उतनी अकुशल नहीं थी जितनी कि इसे बताया गया था। 1880 में नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और अकाल आयोग की रिपोर्टों से भी पारंपरिक खेती के कारण भारत में अक्सर अकाल कायम रहने का मिथक टूटा है।

पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली ने बहु-स्तरित फसलों, मिट्टी के संवर्धन और उत्पाद मूल्य संवर्धन सहित व अधिक उत्पादन वाले इष्टतम मॉडल को अपनाया, जो पर्यावरण के साथ एक स्थिर संबंध भी स्थापित करती है। यह मॉडल खेती का सबसे वैज्ञानिक तरीका था, जो देशी गाय के आसपास विकसित और केंद्रित था, जिससे गांव के सभी समुदायों को 100 प्रतिशत रोजगार भी मिलता था।

रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन मॉडल का आह्वान किया, जो कि भारत में 43 लाख से अधिक किसानों द्वारा 15 से अधिक पारंपरिक खेती के तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाना इस बात का प्रमाण है कि रासायनिक खेती की तुलना में उत्पादन वास्तव में बढ़ता है। ये भूमि अब 'कीटनाशक मुक्त' हैं और किसान की आय में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वैश्विक वैज्ञानिक सबूतों को स्पष्ट रूप से दोहराया गया है कि 'जैविक खेती मौजूदा भूमि से 2050 तक 9 अरब की आबादी को सहजता से खिला सकती है'। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पारंपरिक भारतीय कृषि की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की गई है, जो श्रेष्ठ प्राकृतिक उत्पादों की श्रेष्ठता है और भारत निर्यात व जैविक उत्पादों के लिए विश्व नेता के रूप में है। भारत सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक व परंपरागत कृषि तकनीकों की सफलता और क्षमता का एहसास करते हुए रुपये 4000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी 'परंपरागत कृषि विकास योजना' शुरू की।

कुछ निहित स्वार्थों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का विरोध किया है कि यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। विख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा हाल के कई अध्ययनों ने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करके इस मिथक का भंडाफोड़ किया है।

स्वदेशी जागरण मंच भारत के नागरिकों से अपील करता है कि वे अपने कृषि को विदेशी कंपनियों के चंगुल से बचाने के लिए तरीकों और साधनों की तलाश करें, जो कि संकर/जीएम बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जहरीले जबड़े से भारतीय कृषि को मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार

भी अनुकूल नीतियों का मसौदा तैयार करे।

इसलिए यह आवश्यक है कि पारंपरिक भारतीय तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हों, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को सुनिश्चित किया जाए और एमएसपी में काफी वृद्धि की जाए ताकि कृषि क्षेत्र को तेजी से रिकवरी मोड पर लाया जा सके। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा आम जनता और विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकार से भी इस संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध करती है। □

विदेशी नेस्ले जैसी कंपनियां 8 से 10 प्रतिशत विज्ञापन पर खर्च करती है। जबकि अमूल मात्र 1 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं करता। आरसैप की लड़ाई स्वदेशी जागरण मंच ने की और उसमें विजय प्राप्त की। उसकी बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी के साथ खड़े हैं। स्वदेशी को बढ़ाने के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पाद एवं उत्पादक खड़े करने होंगे, तभी हम विदेशी कंपनियों को मात दे सकेंगे।

गुरुकुल कांगड़ी के माननीय कुलपति **श्री रूपकिशोर शास्त्री** ने कहा कि स्वदेशी की भावना एक सामाजिक संकल्प है। यह हमारे वेद, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा खानपान से जुड़ा है। उन्होंने खादी पहनने का आग्रह किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक फार्मसी खड़ी की है जो कि स्वदेशी रिसर्च पर आधारित है।

श्री अरुण ओझा (अ.भा. संयोजक) ने सत्र 2018-19 में हुए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि आरसीईपी के विरोध में विजय को निरंतर बनाए रखना पड़ेगा। उन्होंने श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी में कार्यक्रम करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में श्री विनोद चौधरी (स्वागताध्यक्ष) ने अपना उद्बोधन दिया तथा परम पूज्य सरसंघचालक जी द्वारा दिए गए उद्बोधन पर आधारित 'दिशा बोध' पुस्तक का विमोचन किया।

श्री भालाजी द्वारा लिखित भारतीय संविधान की पुस्तक का विमोचन श्री अरुण ओझा ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद श्री रामकुमार चौधरी (सह संयोजक उत्तराखंड प्रांत) ने किया। इस प्रकार से उद्घाटन सत्र का समापन हुआ।

आर्थिक उपनिवेशवाद — प्रोफेसर भगवती प्रकाश: विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विकासोन्मुख बाजारों पर नियंत्रण करना चाहती हैं। आज अमेरिका की कुल आय 70 प्रतिशत विदेशों में बिक रहे उत्पादों पर निर्भर है। विदेशी कंपनियां चाहती हैं कि एफडीआई के साथ उनके लिए भारतीय बाजार खुलें। आज देश में 70 प्रतिशत से अधिक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, स्कूटर, सोलर उत्पाद विदेशी कंपनियों के बिक रहे हैं। अतः हमें देश में बढ़ती बेरोजगारी को मिटाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं एवं संस्कृति को अपनाना ही होगा तभी हम लोग एमएनसी का मुकाबला कर सकेंगे।

राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य: स्वदेशी जागरण मंच की 14वीं राष्ट्रीय सभा में उत्तराखंड राज्य की माननीय

राज्यपाल महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने देशभर से आए कार्यकर्ताओं को भारतीय संस्कृति एवं स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को कर्मशील बताया। उन्होंने बताया कि यहां की महिलाएं आचार, स्वेटर आदि बनाती हैं, समाज में कार्य करती हैं, जड़ी बूटियां खोजती हैं और कैसर के इलाज की भी जड़ी बूटियां खोजी हैं। उन्होंने बताया कि हमारा स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा मंच है जो हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटा रहा है। हम स्वदेशी के माध्यम से देश भक्ति का भाव जगा रहे हैं।

डॉ अश्वनी महाजन (अखिल भारतीय सह संयोजक): ने स्वदेशी जागरण मंच के वर्तमान के मुख्य मुद्दों को कार्यकर्ताओं के सम्मुख ओजस्वी शैली में प्रस्तुत किया। मंच के गठन के साथ ही वर्तमान तक स्वदेशी जागरण मंच ने जिन मुद्दों के आधार पर संघर्ष किया, उसकी पहचान देश में दुनिया में अलग से बनी है। भारत ने डब्ल्यूटीओ का संगठित स्वरूप में मुद्दों के आधार पर विरोध किया। परिणामस्वरूप, कृषि व पेटेंट कानून के संबंध में वैश्विक शक्तियां बैकफुट पर आयी हैं और आज हमने आरसीईपी के संबंध में भारत में होने वाले खतरों के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर ज्ञापन, संगोष्ठी के माध्यम से जनजागरण किया। जिससे भारत सरकार आरसीईपी समझौते से हट गई। चीन, जापान अब आरसीईपी के विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए भारत से बार-बार आग्रह कर रहे हैं। यह स्वदेशी जागरण मंच की बहुत बड़ी जीत है।

देश में डिसइनवेस्टमेंट के नाम पर गलत निवेश की योजना बन रही है। उन्होंने कहा कि बीपीसीएल और एयर इंडिया को बेचने की योजना चल रही है। हम इसका विरोध करेंगे।

डॉ. धनपत राम अग्रवाल— बौद्धिक संपदा अधिकार को समझने के लिए दो बातें आती हैं। पहली है बौद्धिक संपदा, यानि जो भी नई सोच या नई खोज जो हमारी बुद्धि में उपजी है और जैसे ही हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो वह हमारी बौद्धिक संपदा कहलाती है। यह अभिव्यक्ति किसी वैज्ञानिक अविष्कार के रूप में भी हो सकती है या फिर किसी कविता, संगीत, गीत अथवा चित्र के माध्यम से भी हो सकती है। अगर यह नई खोज वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित होती है तो उसे कानूनी तौर पर पेटेंट के नाम से जाना जाता है या फिर अगर कविता, गीत, संगीत यानि

प्रस्ताव-2

रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज जीवन का प्राणतत्व है, इसकी वृद्धि हेतु सरकार व समाज दोनों प्रयत्न करें।

भारत अनादिकाल से आर्थिक स्वावलंबन-प्रधान एवं पूर्ण रोजगारयुक्त राष्ट्र रहा है। हमारी अधिकांश जनसंख्या अपने पारिवारिक व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक समृद्धि व स्वावलंबन के मार्ग पर अनवरत अग्रसर रही है और देश के ग्राम व नगर अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए स्वावलंबी रहे हैं। उन्नत व विकेन्द्रित उत्पादन के आधार पर ही ईसापूर्व काल से ही भारत, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन व वस्तु निर्यात का केंद्र रहा है। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसन के अनुसार भारतवर्ष 1500 तक विश्व के एक तिहाई उत्पादों के उत्पादन व निर्यात का वैश्विक उद्गम रहा है। देश के विकेन्द्रित उत्पादन तंत्र का सुदृढ़ आधार नष्ट होने और वैश्वीकरण में आयात उदारीकरण व विदेशी पूंजी निवेश प्रोत्साहन के कारण आज विश्व के विनिर्माणी उत्पादन में भारत का योगदान मात्र 3 प्रतिशत ही है। आज देश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद-स्तरीय उद्यमों में फैलती रूग्णता व उद्यमबंदी से देश में फैलती बेरोजगारी के कारण, कार्यशील आय की जनसंख्या की श्रम शक्ति में भागीदारी 50 प्रतिशत से भी न्यून हो गयी है।

देश में बेरोजगारी एवं संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में सतत गिरावट, अनौपचारिक क्षेत्र के संकुचन, संगठित क्षेत्र में रोजगार के घटते अवसरों के आलोक में आने वाले समय में युवाओं को वृहद स्तर पर अपना स्व-उद्यम स्थापित करने की पहल कर स्वयं रोजगार प्रदाता बनना होगा। देश में कई युवाओं द्वारा अध्ययनोपरान्त स्टार्ट-अप सहित विविध सफल उद्यमों, कृषि क्षेत्र में नई तरीकों के प्रयोगों की स्थापना प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन, स्वरोजगार, स्व-उद्यमों एवं स्टार्ट-अप सहित स्वदेशी पूंजी आधारित उद्यमों की स्थापना के लिए वांछित पारिस्थितिकी तंत्र एवं उचित वातावरण के अभाव में स्वरोजगार सहित सभी प्रकार के रोजगार सृजन में गंभीर गतिरोध भी दृष्टिगोचर होता है। कृषि के बाद रोजगार के सबसे बड़े आधार वस्त्रोद्योग से लेकर सौर ऊर्जा व इलेक्ट्रॉनिक्स पर्यंत विविध क्षेत्रों के उद्यमबंदी भी चिंताजनक है। उद्यमिता विकास की मुद्रा योजना व स्टार्ट-अप संवर्द्धन आदि की 50 से अधिक शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाते हुये युवाओं को वेतनकर्म बनने की अपेक्षा अपना सफल व स्व-संचालित उपक्रम स्थापित कर प्रत्येक ग्राम, कस्बे, नगर व महानगर को नवस्थापित उद्यमों से युक्त करते हुये हर घर-द्वार को रोजगार सृजन का आधार बनाना होगा। स्टार्ट-अप इण्डिया व स्टैण्ड-अप इण्डिया की महत्वकांक्षी योजनाओं के उपरान्त भी इतने विशाल युवाओं वाले देश में आज भी मात्र 50,000 पंजीकृत स्टार्ट-अप हैं और आगामी पाँच वर्षों में भी सरकार इसमें 50,000 की ही वृद्धि की अपेक्षा कर रही हैं। इस गति से उद्यमिता विस्तार से देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 80 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रान्तर्गत व मात्र 6.5 प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र में है। विगत 28 वर्षों में नव-उदारवादी नीतियों के अधीन विदेशी निवेशकों व संगठित क्षेत्र को प्रदत्त लाखों करोड़ की राजकोषीय छूटों, सहायताओं, अनुदानों व उनके लिये घोषित विविध राजकोषीय पैकजों का 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के योगक्षेम के मूल बने हुए आधार अनौपचारिक क्षेत्र को नहीं गया है। इसके विपरीत खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश, ई-कामर्स में विदेशी कंपनियों के प्रवेश रोकड़ सहित व अल्परोकड़ उपयोग प्रोत्साहन योजनाओं आदि से स्वरोजगार क्षेत्र व अनौपचारिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार से आग्रह करता है कि:

1. देश के स्वरोजगाररत वर्गों की समस्याओं का निकट से अध्ययन कर उनके संरक्षण, समर्थन व सम्बल प्रदान करे। इस हेतु स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों व परिवारों का विश्वसनीय और तथ्यात्मक डेटा बैंक व विस्तृत प्रतिवेदन भी विकसित करे। रोजगार निर्माण हेतु कोई नियामक भी बनाया जा सकता है।
2. स्वरोजगार को प्रभावित करने वाली आर्थिक नीतियों को उलटकर, उसे बढ़ावा देने की प्रभावी योजना लाये। स्वरोजगाररत एवं मुद्रा आदि ऋणों के पात्र लोगों को ऋण देने हेतु चयन बैंकों पर छोड़ने के स्थान पर इच्छुक लोगों का स्वतंत्र पंजीयन, चयन व अनुशंसा करने की प्रक्रिया विकसित की जाये।
3. स्वरोजगाररत व अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूचीयन, पंजीयन, विपणन व संवर्द्धन आदि के लिए ऐसा डिजिटल विनिमय (Digital Exchange) विकसित करे जिस पर उनकी वस्तुओं व सेवाओं का लाभ पूर्ण विपणन हो सके।

मंच का आग्रह है कि सरकार स्व-उद्यम व स्टार्ट-अप सहित सभी प्रकार के स्वरोजगार में संलग्न वर्गों जिसमें फेरीवाले, रिक्शा वाले, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार, हस्तशिल्पी, टिफिन सेवा प्रदाता, सौन्दर्य विशेषज्ञ (ब्युटिशियन) आदि सभी स्वरोजगाररत वर्गों के सूचीयन, संवर्द्धन एवं उनके उचित योगक्षेम की वृहद स्तर पर आयोजन कर इसका अविलम्ब क्रियान्वयन करे।

स्वदेशी जागरण मंच समाज से भी आग्रह करता है कि -

- युवा वर्ग सहित सभी श्रेणीयों के समाजजन विविध प्रकार के स्व-उद्यम व स्वरोजगार के अवसरों का उपयोग कर न केवल अपने रोजगार का सृजन करें, वरन अन्य भी रोजगार खोजने वाले अधिकतम लोगों के लिए रोजगार प्रदाता बनें। "We will not be jobseeker, we will be job provider" यह विचार देश भर के युवाओं का प्रेरक-दिशा बोध हो, इस हेतु जनजागरण करना होगा।
- स्थानीय व स्वदेशी ही खरीदो का आग्रह भी रोजगार, लघु व स्थानीय उद्योगों को बढ़ायेगा व रोजगार बढ़ेगा। →

- कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर बेचना, व कृषि की सहायक गतिविधियां (गौ, पशुपालन, मधुमक्खी, मुर्गी पालन आदि) भी ग्रामीण क्षेत्र की आय व रोजगार बढ़ाती है।

मंच सभी कार्यकर्ताओं का भी आवाहन करता है कि सभी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय स्व-उद्यम संकुलों और संपूर्ण समाज में स्व-उद्यम व स्वरोजगार की प्रेरणा जगायें और उद्यम उष्मायन केन्द्रों अर्थात् इनक्यूबेशन सहित उद्यमिता विकास की गतिविधियों उद्यमिता विकास अभ्यास वर्गों आदि के माध्यम से समाज को व्यापक स्तर पर स्वरोजगार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा एवं अधिकतम सहकार प्रदान करें। □

किसी पेटेंट आदि के रूप में होती है तो उसे कॉपीराइट कहते हैं। इस तरह के आविष्कार या नई कला का वैज्ञानिक ढंग से रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो उसे बौद्धिक संपदा अधिकार अथवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) कहते हैं।

वरिष्ठ प्रचारक एवं स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य श्री **सरोज मित्र** ने दत्तोपंत टेंगड़ी के जीवन को विभिन्न उदाहरणों द्वारा कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। राष्ट्रवादि दत्तोपंत टेंगड़ी भारत के चिरंजीवी विकास हेतु चिंतनशील रहते थे। टेंगड़ी जी ने इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण करने वाले संगठनों की स्थापना की। उन्होंने मजदूर संघ, किसानों के बीच में किसान संघ तथा स्वदेशी संस्कृति अपनी क्षमता पर खड़ा हो, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। टेंगड़ी जी जब रूस जाकर 1968 में लौटे, तो उन्होंने कोलकाता में घोषणा की, कि कम्युनिज्म रिवर्स गियर में आ चुका है। वह दूरदृष्टा थे। कोलकाता में उनके साथ सुनील घोष (सुभाष चंद्र बोस के मित्र) मिले, तब घोष ने कहा कि टेंगड़ी जी सुभाष चंद्र बोस से अधिक राष्ट्रीय चिंतक है।

टेंगड़ी जी ने ह्यूमनिज्म पर काम किया। वे मानव मात्र के कल्याण के लिए बात करते थे। इससे प्रभावित होकर कम्युनिस्ट विचारक श्री डांगे ने भी उनकी प्रशंसा की, कि टेंगड़ी जी बहुत श्रेष्ठ चिंतक है।

1976 में उन्होंने रिवॉल्यूशन पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन कभी हिंसक नहीं होना चाहिए अर्थात् शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर थे। वे कार्यकर्ता पर पूर्ण विश्वास करते थे और कार्यकर्ता की कोई गलती होने पर भी उत्तरदायित्व स्वयं लेते थे।

विकास की अवधारणा: अखिल भारतीय संगठक श्री **कश्मीरी लाल** ने कार्यकर्ताओं को माननीय दत्तोपंत टेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी हेतु वर्ष भर के लिए अपने को विषय के साथ तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें विकास की अवधारणा पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में विषय लेते समय दत्तोपंत टेंगड़ी जी और भारत निर्माण तथा राष्ट्र की अवधारणा, जिसमें देश की समृद्धि का समुचित वर्णन हो, लेना चाहिए। अ.भा. संगठक ने आग्रह किया कि हमें दत्तोपंत टेंगड़ी जी की पुस्तिका 'विकास की अवधारणा' को पढ़ना चाहिए। टेंगड़ी जी आधुनिकीकरण के पक्षधर थे,

पर वे कहते थे कि Modernization without westernization होना चाहिए। टेंगड़ी जी कहते थे कि हम विदेशों की नकल न करें। हमारा विकास 'गरीबी कैसे हटे' इसके लिए हो।

देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। यह तभी संभव है जब देश में विकास अंत्योदय से शुरू हो। श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि विकास के लिए 6 सूत्र जरूरी है। प्रथम, विकास की शुरुआत विकेंद्रीकरण से हो। द्वितीय, यह विकास गांव आधारित हो। गांव बचेगा तो देश बचेगा। महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना गरीब वर्गों से प्रारंभ होती है। तृतीय, उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा, प्राकृतिक पूजक है। माताएं बहनें प्रातः उठते ही वृक्षों को जल चढ़ाते थीं। अतः विकास पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए होना चाहिए। अंत में श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि हमारे देश की परंपरा धर्माधिष्ठित विकास की रही है। अर्थात् मानव मात्र के कल्याण का आधार चिरंजीवी विकास है। आपने एकात्म मानव विकास मात्र के विकास को सच्चा विकास बताया है। जिसमें मानवता बचेगी, प्रकृति बचेगी, पृथ्वी बचेगी, यही स्वदेशी का मूल मंत्र है। विकास की अवधारणा है।

आम सभा: 14वीं राष्ट्रीय सभा की स्वदेशी संदेश यात्रा के पश्चात आमसभा का कार्यक्रम हुआ। इसके मुख्य अतिथि श्री सतपाल जी महाराज, केबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार रहे। श्री मोहन जी गांववासी ने अध्यक्षीय उद्बोधन किया। कार्यक्रम में कर्नाटक प्रांत के सह संयोजक श्री एस. बी. पाटिल ने आरसीईपी में भू-राजनीति की बात कही। उन्होंने कहा कि आरसीईपी पर हस्ताक्षर न करके चीन की भू-राजनीति पर रोक लगाई है। कार्यक्रम में अनंदाशंकर पाणीग्रही ने कहा कि स्वदेशी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। यह आम आदमी, अंतिम व्यक्ति की उन्नति का मार्ग है। डब्ल्यूटीओ व एमएनसी भारत के व्यक्ति को विकसित नहीं होने देना चाहती। इसलिए हमें इनके उत्पादों का बहिष्कार करना है। हम भारतीयों के स्वावलंबी बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं। स्वदेशी का मतलब है स्वावलंबी भारत।

कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच की महिला प्रमुख

प्रस्ताव-3

डेटा संप्रभुता-डेटा स्थानीयकरण-डिजिटल राष्ट्रवाद: समय की मांग

‘डेटा’ चौथी औद्योगिक क्रांति का नया आधार है और यदि डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक तेज एल्गोरिथम के साथ वह करने की क्षमता है, जिसकी मानव अभी तक कल्पना भी नहीं कर पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सत्ता के लिए एक कच्चा माल है, प्रभाव बढ़ाने का स्रोत है और मानवता को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। जब वैश्विक शक्तियां इस डेटा को कब्जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, भारत जो दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा; इंटरनेट उपभोक्ताओं का पांचवां हिस्सा है, चुप नहीं बैठ सकता।

भारत को न केवल देश में इक्ठ्ठा किए डेटा के स्वामित्व की ही, बल्कि देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत डेटा की गणना करने के अधिकार की भी आवश्यकता है। डेटा व्यवहार को समझने और व्यवहार को प्रभावित करने के साथ-साथ कुशल रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन की कुंजी है। यह भविष्य है, यह वर्तमान है और देश को इस अवसर को पाने के लिए जागना होगा।

यदि हम अपने आस-पास देखें तो रोबोट आधारित उत्पादन और मशीन लर्निंग के लिए डेटा एक कुंजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को आकार दे रही है। ई-कॉमर्स फर्म और प्लेटफार्म डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा को नियंत्रित कर रहे हैं और इसके माध्यम से वे एकाधिकारिक लाभ उठा रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने ही आचरणों और उपक्रमों के व्यवहार और समाधान जानने के लिए डॉलरों या यूरो में भुगतान कर सकते हैं? चौथी औद्योगिक क्रांति या डिजिटल औद्योगिक क्रांति की सफलता डेटा तक पहुंच पर निर्भर करती है।

विकसित देश अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा शक्ति को मजबूत बनाने हेतु डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि डेटा का मुक्त प्रवाह विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंधों को असीमित बना देगा और विकासशील देश के उद्यमों को नुकसान की स्थिति में डाल देगा। इसलिए डेटा का विनियमन बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटॉड) की रिपोर्ट 2018 कहती है, “देशों के लिए डेटा को नियंत्रित करना और अपने डेटा का उपयोग/सांझा करना और उसके प्रवाह को विनियमित करना महत्वपूर्ण है।” इसके अलावा अंकटॉड की रिपोर्ट का यह निष्कर्ष है, “आधार रेखा यह है कि विकासशील देशों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदत्त विकास की संभावनाएं आसानी से विलुप्त हो जाएंगी, यदि उन्हें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल क्षमताओं को संवर्धित करने हेतु अपनी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों को तैयार करने हेतु लचीलापन और नीतिगत अवसर नहीं दिया जाता।”

हमने हाल ही में क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की वार्ताओं, यहां तक की संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में अधिकांश ध्यान हमारे डेटा को नियंत्रित करने और उसके संबंध में कानून बनाने के हमारे अधिकार को समाप्त करने की ओर है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आरसीईपी वार्ताओं से अलग कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ भी डेटा संप्रभुता के आत्मसमर्पण के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आर्थिक हितों के साथ-साथ, देश की सीमाओं से परे महत्वपूर्ण डेटा का प्रवाह और स्थानीय सर्वरों की अनुपस्थिति, देश की सुरक्षा के लिए भी भारी खतरा उपस्थित करती है। विकसित देश व्यापार एवं निवेश नियमों का हवाला देते हुए डेटा के मुक्त प्रवाह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2019 में विश्व व्यापार संगठन के कई देशों ने व्यापार संबंधित ई-कॉमर्स विषय पर वार्ताएं शुरू कर दी हैं। भारत इस प्रकार की किसी भी वार्ता में लिप्त होने से अलग रहा है। जी-20 सम्मेलन में भी, 24 देशों द्वारा हस्ताक्षरित डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओसाका घोषणा पर, डेटा के मुक्त प्रवाह के लिए इसके निहितार्थ के कारण हस्ताक्षर करने के लिए भी भारत ने मना कर दिया था।

हालांकि व्यक्तियों की निजता कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बढ़ने के साथ, डेटा अधिकारों को केवल निजता या अन्यथा केवल एक व्यक्तिवादी ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। मूल्यवान डेटा अक्सर समष्टि, समूह या अज्ञात रूप में होता है। और इसलिए कॉरपोरेट की अधिकाधिक लाभ कमाने की लालशा डेटा के एक आर्थिक संसाधन पर सामुहिक अधिकार की अवहेलना नहीं की जा सकती। यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय समाज, शहर, गांव या पड़ोस समुदाय और उसके साथ-साथ कार्मिकों के समुदाय/वर्ग, व्यापारी एवं उत्पादक इन सबका उस समस्त डेटा पर मौलिक आर्थिक अधिकार है, जो उन्होंने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर दिया है। जब तक इस तरह के नए वैकल्पिक ढांचे विकसित नहीं किए जाते, तब तक मुक्त व्यापार समझौतों के प्रसार और साथ ही साथ ई-कॉमर्स पर विश्व व्यापार संगठन सरीखे बहुपक्षीय संगठनों में ‘डेटा के वैश्विक मुक्त प्रवाह’ सिद्धांत पर आधारित हो रहे प्रयासों से देश मूल्यवान डेटा पर अपना स्वामित्व खो देगा। →

→ स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि :

1. भारत सरकार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में डेटा संप्रभुता पर बातचीत करने से बचे।
2. डेटा को न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत संग्रहित किया जाए, बल्कि उसकी गणना भी भारत में ही हो।
3. चाहे डेटा व्यवसायिक हो, रणनीतिक हो या प्राथमिक ही हो, यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका संरक्षण होना ही चाहिए।
4. डेटा की निजता जरूरी है, निजता को परिभाषित करने और इसके हनन की जबाबदेही करने वाले कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाए।
5. यह समझते हुए कि कच्चे रूप में डेटा का अधिक उपयोग नहीं हो सकता, अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक कौशल के साथ कार्यबल को प्रोत्साहित किया जाए।
6. सरकार को उन एप्स की पहचान करनी चाहिए, जो अनावश्यक डेटा एकत्र कर रहे हैं और आवश्यक अनुमतियों से ज्यादा चाहते हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस क्षेत्र में काम कर रहे स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
7. भुगतान गेटवे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सेवा समूह कर्ताओं इत्यादि में भारतीय विकल्पों को प्रोत्साहन एवं समर्थन दिया जाए।□

श्रीमती अमिता पत्की, भारतीय मजदूर संघ के **श्री पवन कुमार** ने अपनी बात रखी।

अ.भा. विचार विभाग प्रमुख **श्री सतीश कुमार** ने स्वदेशी आंदोलन को सांस्कृतिक उत्थान का मूलमंत्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1850 में श्री राम सिंह फूका ने पंजाब में प्रारंभ की। 1882 में श्री बंकिमचंद्र चटर्जी ने वन्देमातरम के माध्यम से स्वदेशी के भाव को जागृत किया। 1905 में वीर सावरकर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन को आम आदमी तक पहुंचाया। 1920 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी चरखे के माध्यम से अंग्रेजों के विरोध में जनता को खड़ा किया।

अब समय आ गया है कि भारत स्वदेशी के माध्यम से खड़ा हो रहा है। हम सब कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन को घर-घर तक पहुंचाना है। अंत में श्री सतीश कुमार ने कहा कि शताब्दी वर्ष में टेंगड़ी जी के सपनों को हम साकार करेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि **श्री सतपाल जी महाराज** ने स्वदेशी जागरण मंच की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच भारत के आम नागरिक के विकास की बात कर रहा है। उन्होंने ई-कॉमर्स को देश के व्यापारियों के लिए घातक बताया और कहा कि हमें अपने व्यापारियों को बचाने के लिए ई-कॉमर्स को रोकना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में मजबूत होगी। सतपाल महाराज ने देश को आयुर्वेद, स्वदेशी तथा तीर्थाटन के माध्यम से विकसित करने का आह्वान किया।

स्वदेशी जागरण मंच की आगामी कार्यदिशा: आगामी कार्यक्रम के लिए माननीय कश्मीरी लाल ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में जाकर स्वदेशी के राजदूत के जैसे कार्य करें। परम पूज्य सरसंग्रहालक जी के विजयादशमी उत्सव पर दिए गए मार्गदर्शन पर प्रकाशित पुस्तक **‘दिशा बोध’** का सभी कार्यकर्ताओं को पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि दत्तोपंत टेंगड़ी जी की

जन्म शताब्दी पर हम सभी मिलकर ‘विकास की अवधारणा’ व राष्ट्र की अवधारणा पर टेंगड़ी जी के विचारों का अध्ययन करें। हम 7 निम्न बिंदु ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं को संपर्क करें। ये बिंदु हैं— पत्रक, पत्रिका, प्रचार, प्रदर्शन, प्रवास, प्रबोधन और पैसा (धन संग्रह)।

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देने से पहले उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस शताब्दी समारोह में न्यूनतम 15 दिन का समय स्वदेशी विस्तारक बनकर दें। आगामी कार्यक्रमों के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए निम्न योजना का आग्रह किया।

1. 14वीं राष्ट्रीय सभा के प्रस्तावों को पढ़ना, पढ़ाना, समाचार पत्रों में देना।
2. प्रत्येक जिला केंद्रों पर टेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के उद्घाटन कार्यक्रम करना।
3. जनवरी-फरवरी माह में विकास की अवधारणा पर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी करना, प्रबोधन करना।
4. 23 मार्च भगत सिंह के शहीदी दिवस पर युवाओं की रैलियां निकालना।
5. जून-जुलाई में राष्ट्रीय विचार वर्ग आयोजित करना। जिसमें प्रत्येक सहभागी, टेंगड़ी जी का साहित्य अवश्य पढ़कर आयें।
6. 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह में प्रत्येक जिले, स्कूल और कालेजों में पत्रक वितरण करना और उद्बोधन भी देना। इस हेतु नए लोगों को जोड़ना।
7. प्रमुख स्तंभकार लेखकों को राष्ट्रऋषि दत्तोपंत टेंगड़ी जी का साहित्य देना।
8. राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना। टेंगड़ी जी का साहित्य देना तथा सकारात्मक व्यक्तियों की सूची बनाना।
9. अपने घर में टेंगड़ी जी का चित्र लगाकर जन्मशताब्दी का कार्यक्रम घर में करना तथा स्वदेशी संकल्पित परिवारों का निर्माण करना।

रणनीतिक विनिवेश राष्ट्र हित में नहीं

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) का रणनीतिक विनिवेश न केवल एक अविवेकी व्यावसायिक निर्णय है, बल्कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ भी है। यह न केवल भारत के लोगों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मालिक हैं, को इन उद्यमों में परिसंपत्तियों और पूंजी निवेश के उचित मूल्य से वंचित करता है, बल्कि यह उन लोगों को भी अनुचित लाभ देता है जो इन्हें खरीदने का इरादा रखते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, लेकिन विनिवेश के नाम पर हम बहुराष्ट्रीय निगमों और कॉरपोरेट घरानों को राष्ट्रीय संपत्ति सौंपने की योजना का विरोध करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है—उनकी क्षमता, रणनीतिक आवश्यकता, टर्नअराउंड संभाव्यता, बाजार उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विनिवेश रणनीति की आवश्यकता है। इस समय राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया और तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल का रणनीतिक विनिवेश करने की योजना बनायी जा रही है। एयर इंडिया को पुनर्गठन और पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता है, विनिवेश की नहीं। ये भावनात्मक स्थिति नहीं हैं, लेकिन एक शुद्ध व्यावसायिक आवश्यकता है। एयर इंडिया के वित्तीय और अन्य दस्तावेजों की करीबी जांच से पता चलता है कि एयर इंडिया के ऋण और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन से न केवल कंपनी की देनदारियों को कम किया जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीय वाहक को मुनाफे में वापस लाया जा सकता है। घाटे की एक बड़ी वजह कर्ज की मूल एवं ब्याज की अदायगी है। यह ऋण गलत इरादों के साथ खराब निर्णय लेने के कारण लिया गया था। एयर इंडिया को खराब संपत्ति कहना वास्तव में दर्दनाक और अनुचित है। भारत जैसे विकासशील देश को रणनीतिक और बाजार संतुलन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वाहक की आवश्यकता है।

इस बीच, बीपीसीएल का रणनीतिक विनिवेश निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारिक निर्णय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नियमित रूप से मुनाफा कमा रही है। उनकी रिफाइनरियों का सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) वैश्विक बाजारों के समकक्ष है।

रणनीतिक निवेश से कोई लाभ नहीं: निजीकरण के बारे में समर्थक कई बार हिंदुस्तान जिंक के मुनाफे का उदाहरण देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीपीसीएल पहले से ही उदारीकृत वातावरण में चल रही है और एक पेशेवर रूप से संचालित उद्यम है। उत्पाद मूल्य निर्धारण से लेकर संचालन तक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। यदि सरकार अपने इक्विटी को कम करना चाहती है, तो इसे निष्पादित करने के लिए सबसे अच्छी जगह शेयर मार्केट है। बीपीसीएल मुनाफे में है और पहले से ही अच्छा लाभांश दे रही है और वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। शेयर बाजार न केवल इक्विटी के लिए बेहतर मूल्य देगा, बल्कि बीपीसीएल के अच्छे प्रदर्शन का लाभ छोटे निवेशकों को भी मिलेगा। इसके विपरीत भारत द्वारा बीपीसीएल के विनिवेश की घोषणा के बाद 'सऊदी अरामको' इसकी संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है। यह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि खतरनाक भी है। राष्ट्रीय भावनाओं और कड़ी मेहनत के साथ बनाई गई संपत्ति विदेशी तेल कंपनियों के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। उनके बीपीसीएल की खरीद केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक आंकड़े के रूप में है। रणनीतिक 'बिक्री' बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रणनीतिक खरीद बन रही है।

इसी तरह, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की रणनीतिक बिक्री भी समझदारी पूर्ण व्यापारिक निर्णय नहीं हैं। ये दोनों उद्यम न केवल बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बल्कि भारतीय उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स को और तेज करने की सरकार की योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भी हैं। पिछले पांच वर्षों में, भारत ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारे समेत सड़क और माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। सीसीआई के इस समय एक निजी हाथ में जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, एससीआई एकमात्र कंपनी है, जो भारतीय ध्वज के साथ दुनिया भर में जहाज चलाती है। अधिकांश निजी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए स्वामित्व मुख्य भूमि भारत को नहीं रखते हैं। एससीआई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को अगले पाँच वर्षों में दोगुना करने के लिए भारत का अभिन्न उद्यम है।

स्वामित्व को बेचकर पैसा इकट्ठा करना और भविष्य में होने वाली आजीवन कमाई छोड़ देना एक बुद्धिमान व्यापार निर्णय नहीं होगा, खासकर, जब सरकार कह कर रही है कि उनका कर संग्रह लक्ष्य से मेल नहीं खा रहा है। वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान ने संकेत दिया कि सरकार पांच सार्वजनिक उपक्रमों में अपने इक्विटी बेचकर 1 लाख करोड़ रुपये की निकासी करने जा रही है। सरकार ने पहले ही विनिवेश के लिए अन्य 28 सार्वजनिक उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को तैयार कर लिया है। सूची में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल), पवन हंस, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) शामिल हैं।

सरकारी इक्विटी को बेचने के तरीकों और समय पर एक बड़े सार्वजनिक विचार-विमर्श और बहस की आवश्यकता है। सरकार को वाशिंगटन सर्वसम्मति के जाल में पड़ कर कुछ कॉर्पोरेट घरानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इक्विटी बेचने के बजाय दीर्घकालिक समाधानों को देखना चाहिए। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बेचनी चाहिए। विनिवेश की वर्तमान योजना कुछ सलाहकारों, कुछ व्यावसायिक घरानों से प्रभावित नौकरशाहों के षड्यंत्रों का परिणाम है। आज इन कदमों का विरोध करने और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करने का समय है। सरकार को हितों के टकराव और भारतीय परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के आरोपों पर गौर करना चाहिए। →

आवरण कथा

→ स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि—

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए। अगले पांच वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने और संबंधित वर्षों में इसे और तेज करने की कल्पना को ध्यान में रखते हुए पीएसई के मूल्यांकन के जाँच की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट कुछ सलाहकारों के निहित स्वार्थों का काम है, उन्हें इस काम से दूर रखा जाना चाहिए। नई रिपोर्ट को ऐसे लोगों के एक नए समूह के साथ बनाया जाना चाहिए, जो न केवल पूर्व धारणाओं से मुक्त हैं, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए खुला विचार रखते हैं।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्मूल्यांकन, उनकी बैलेंस-शीट, ...भविष्य में रणनीतिक आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाए।
3. व्यापक सार्वजनिक उपक्रम नीति बनाई जाए। इन उद्यमों की भूमिका को परिभाषित करते हुए भारत को और अधिक मजबूत बनाने में उनके योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए।
4. एयर इंडिया, बीएसएनएल आदि कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जो देश की रणनीतिक जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। इन सार्वजनिक उपक्रमों को पुनः बेहतर किया जा सकता है। इसे पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
5. लाभदायक सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश पर एक राष्ट्रीय बहस, समय की आवश्यकता है। एचपीसीएल के पिछले विनिवेश पर एक श्वेत पत्र की आवश्यकता है, जहां ओएनजीसी ने इक्विटी का अधिग्रहण किया था। इससे एचपीसीएल के संचालन को कैसे लाभ हुआ है? बीपीसीएल के निजीकरण के लाभ के बारे में सरकार को बताना चाहिए। सरकार को सलाह देने के लिए और बाद में इक्विटी को उतारने के लिए उनकी सहायता करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के तरीके की जांच करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत की संपत्ति पर कब्जे को प्रभाव देने के लिए 'हितों के टकराव' और गुट के गठन की आशंका व्यक्त की जा रही है।
6. विशेष व्यवसाय घरानों को लाभान्वित करने के लिए रणनीतिक बिक्री का भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में पारदर्शी तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। किसी भी दिशा में जाने से पहले सभी हितधारकों के अधिकारों और विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। □

प्रतिनिधिगण: देश भर से विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया — केरल—20, तेलंगाना—03, आंध्र प्रदेश—23, तमिलनाडू—08, कर्नाटक—25, विदर्भ—22, प. महाराष्ट्र—03, कोकण—02, गुजरात—39, मध्य भारत—47, महाकौशल—24, मालवा—23, छत्तीसगढ़—04, चित्तौड़—19, जोधपुर—30, जयपुर—38, जम्मू कश्मीर—25, पंजाब—15, हिमाचल प्रदेश—43, हरियाणा—60, दिल्ली—85, प.उ.प्र.—42, अवध—04, पूर्वी उ.प्र.—96, उत्तराखंड—07, उड़ीसा—83, प. बंगाल—57, झारखंड—78, उ.बिहार—14, द.बिहार—40, सिक्किम—01, कुल—980

दायित्व: स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री अरुण ओझा जी अब अखिल भारतीय सहसंयोजक रहेंगे तथा श्री आर.सुन्दरम जी अब स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक का दायित्व निभायेंगे। ऐसे ही आयुवृद्धि के कारण अब तक अ.भा. सहसंयोजक प्रो. बी.एम.कुमारस्वामी अब रा.प. सदस्य रहेंगे। राष्ट्रीय सभा में निम्नलिखित स्वदेशी कार्यकर्ताओं के दायित्व की भी घोषणा हुई —

- **तमिलनाडू**— श्री पी. पूमारन—मदुरै (रा.प. सदस्य)
- **आंध्र प्रदेश**— श्री कृष्णभगवान (सिर्फ प्रांत संपर्क प्रमुख रहेंगे)।
- **कर्नाटक**— अब से दो प्रांत रहेंगे 1. दक्षिण कर्नाटक, 2. उत्तर कर्नाटक, श्री जगदीश इन दोनों प्रांतों के संगठक व तेलंगाना के संपर्क प्रमुख रहेंगे।

श्री मंजूनाथ (प्रांत संयोजक—द. कर्नाटक), श्री विजय कृष्णा (प्रांत सहसंयोजक—द. कर्नाटक), श्री एस.सी. पाटिल (प्रांत संयोजक—उत्तर. कर्नाटक), श्री श्रीनिवास (प्रांत संपर्क प्रमुख, द. कर्नाटक), प्रो. सत्यनारायण (प्रांत सह विचार विभाग प्रमुख व रा.प. सदस्य)

- **मध्य भारत**— श्री बाबूदास (केवल रा.प. सदस्य), श्रीकांत बुधोलिया (सह प्रांत संयोजक)
- **महाकौशल**— श्री संजीव डे (प्रांत संपर्क प्रमुख व रा.प. सदस्य)
- **मालवा**— श्री सुरेश बिजोलिया (सिर्फ रा.प. सदस्य), श्री हरिओम वर्मा (प्रांत संयोजक), श्री दिलीप चौहान (सह प्रांत संयोजक)
- **राजस्थान क्षेत्र**: डॉ. सतीश आचार्य (क्षेत्र सह संयोजक, राज.),
- **चित्तौड़ प्रांत**— श्री पुरुषोत्तम शर्मा (प्रांत संयोजक), श्री महेश नवहाल (प्रांत सहसंयोजक), श्री राजेन्द्र शर्मा—कोटा (प्रांत सहसंयोजक)
- **जयपुर प्रांत**— श्री सुरेश खंडेलवाल (केवल रा.प. सदस्य)
- **पंजाब**— डॉ. मनजीत बंसल (प्रांत संपर्क प्रमुख व रा.प. सदस्य), श्री अरविन्द (महानगर संयोजक व रा.प. सदस्य), श्री मधुर महाजन—चंडीगढ़ (महानगर संयोजक व रा. प. सदस्य)
- **हरियाणा**— श्री अनिल कुमार—हिसार (विभाग संपर्क प्रमुख व रा.प. सदस्य)



- **दिल्ली**— श्री सुशील पांचाल (सिर्फ रा.प. सदस्य), श्री रविन्द्र सोलंकी (सिर्फ रा.प. सदस्य)
- **अवध**— डॉ. मनोज अग्रवाल—लखनऊ (सह प्रांत संयोजक)
- **पूर्वी उ.प्र.**— श्री शारदानंद त्रिपाठी (प्रांत सह संघर्षवाहिनी प्रमुख)
- **उ. बिहार**— श्री मणिकांत जालान (विचार विभाग प्रमुख, जिला बेगूसराय), श्री पवन कुमार (सह विचार विभाग प्रमुख, बेगूसराय)
- **द. बिहार**— श्री प्रवीण दूबे (प्रांत विचार विभाग प्रमुख व रा.प. सदस्य), श्री लाल बहादुर दुबे (सह प्रांत संयोजक)
- **झारखंड**— श्री पुतकर हैम्बर्ग (सिर्फ रा.प. सदस्य)
- **बंगाल**— डॉ. समीर चटर्जी (प्रांत विचार विभाग प्रमुख व रा.प. सदस्य), डॉ. भाग्योद्धर भट्टाचार्य (रा.प. सदस्य), श्री अशोक पाल चौधरी (रा.प. सदस्य), श्रीमती दुलाली दसक (रा.प. सदस्य), श्री श्यामल कांतिधर (रा.प. सदस्य)
- **सिक्किम**— श्री शिरीष खांडे—नामची (सह प्रांत संयोजक)
- **असम**— श्री प्रशांत भोइयां अब सिर्फ राष्ट्रीय परिषद् सदस्य रहेंगे।

समापन समारोह: समापन समारोह में अखिल भारतीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया तथा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता डॉ. राजीव कुमार, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री रामकुमार सहित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। स्वदेशी जागरण मंच की 28 वर्षों की यात्रा के साक्षी श्री अरुण ओझा ने कहा कि भारत के आर्थिक क्षेत्र का स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय संगठन सबसे बड़ा है। इस पर हमें गौरव है। यह कार्यकर्ताओं की तपस्या से हुआ है। भारत की परंपरा और पश्चिमी संस्कृति में अंतर बताते हुए कहा कि हम अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता करते हैं, वहीं पश्चिम के लोग सर्वोत्तम का चयन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। देश में इसके कारण

हमारी परिवार प्रणाली पर आक्रमण हो रहे हैं। परिवारों में पश्चिमी प्रभाव देखा जा रहा है व रहने का तरीका बदल रहा है। जिससे भारतीय संस्कृति पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारी संस्कृति देश की आत्मा है और इसे बचाना है। श्री घनश्याम दास बिडला के वाक्य को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हमें अपनी शक्ति पर खड़े होना है। आज दुनिया को भारत की जरूरत है। हम वनराज हैं। अपनी शक्ति को हम पहचानते हैं। हम सब इसको मिलकर नई ताकत के रूप में खड़ा करेंगे। *जो नहीं हुए पूर्ण काम* पंक्ति के साथ ही सब कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए अपना उद्बोधन समाप्त किया।

मंच पर प्रो. भगवती प्रकाश ने श्री अरुण ओझा के स्थान पर श्री आर. सुन्दरम को अखिल भारतीय संयोजक के नये दायित्व की घोषणा की। श्री आर. सुन्दरम ने अपने उद्बोधन में श्रद्धेय बाला साहब देवरस जी को उद्धृत करते हुए कहा कि अपने पास यह देव दुर्लभ टोली है, जो समाज जीवन में परिवर्तन करेगी। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती संयोजकों डॉ. एम.जी. बोकरे, श्री पी.मुरलीधर राव, श्री अरुण ओझा के प्रयत्नों को स्मरण किया व प्रो. भगवती भगवती प्रकाश, श्री कश्मीरी लाल तथा अन्य महानुभावों को संबोधित होकर कहा कि इन सब लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए पूज्य टेंगड़ी जी की नीतियों के अनुसार स्वदेशी जागरण मंच को आगे बढ़ायेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष भारत के अर्थिक क्षेत्र के लिए बड़े चुनौतिपूर्ण होंगे। मंच को इसके लिए तैयार रहना होगा। देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व रोजगार खड़ा करने हेतु व्यापक प्रयत्न भी करने होंगे। भारत में श्री दत्तोपंत टेंगड़ी जी के मार्ग पर चलते हुए हम राष्ट्र प्रथम, स्वदेशी प्रथम के सिद्धांत को अपनायेंगे। हम सबको भारत को एक महाशक्ति बनाने का संकल्प करना है। भारत माता की जय।

प्रस्तुति: सतीश कुमार (स्वदेशी जागरण मंच, दिल्ली)

‘घाटे में न बिके, एयर इंडिया-बीपीसीएल’

‘कर-दाताओं के पैसों और वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को औने-पौने दाम में व्यावसायिक घरानों को नहीं बेचा जाना चाहिए।’ स्वदेशी जागरण मंच ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों के रणनीतिक बिक्री को गैरकानूनी तथा राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया है।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन रेडिफ डॉट कॉम की शोभा वारियर से इस संबंध में खुलकर बातचीत करते हुए कहा है कि ‘सार्वजनिक कंपनियां हमारी रणनीतिक संपत्ति हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए।’

आप सरकार के पांच सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के फैसले का विरोध करते हैं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि आप विनिवेश के खिलाफ हैं?

नहीं। हमारा संकल्प साफ कहता है कि स्वदेशी जागरण मंच विनिवेश के खिलाफ नहीं है। शुरुआत से ही, हम निजीकरण के पक्षधर रहे हैं, लेकिन हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को अत्यधिक महत्व देते हैं। हमें कुछ मामलों में बड़े पैमाने पर भी जाना होगा, उदाहरण के लिए, एयरलाइंस, रिफाइनरियां आदि। इसलिए भी हम विनिवेश या निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम रणनीतिक विनिवेश के विचार का प्रबल विरोध करते हैं। हमने एनडीए (प्रथम) के दौरान भी रणनीतिक रूप से किये जाने वाले विनिवेश का विरोध किया था।

2001-02 में वाजपेयी सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अच्छे परिणामों के साथ विनिवेश को अंजाम दिया था।

उस समय भी हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। खरीदार भी बहुत सीमित थे। इसलिए हमें लगा कि सरकार को अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। इसीलिए तब भी हमने सुझाव दिया था कि सरकार को इक्विटी रूट के माध्यम से ही विनिवेश करना चाहिए।

सन् 2014 में जब एनडीए (द्वितीय) सत्ता में आयी, तो हमने तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बातचीत में सहमति व्यक्त की थी कि विनिवेश को लेकर एनडीए (प्रथम) ने जो किया था, वह एक विवेकपूर्ण तरीका नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। उन्होंने हमें बताया कि आगे जब भी वे विनिवेश के लिए जाएंगे, वे केवल इक्विटी मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे।

आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने अपने पहले पाँच वर्षों (2014-19) में जो कुछ भी किया वह सब इक्विटी रूट के माध्यम से ही किया।

लेकिन मोदी सरकार के अंतिम चरण में, जब उन्होंने एयर इंडिया में विनिवेश की बात की, तो हमने कहा था कि हम एयर इंडिया में विनिवेश करने के विचार के खिलाफ नहीं थे, अगर यह इक्विटी मार्ग के माध्यम से किया जाता।

अगर उचित तरीके से विनिवेश किया जाता है और उसका मूल्यांकन भी अच्छा-से-अच्छा हो तथा अधिकाधिक बोलीदाता प्रक्रिया में शामिल किये जाते हो, तो रणनीतिक बिक्री में क्या समस्या है?

यदि आप बीपीसीएल के मामले को देखें, जिसमें अब विनिवेश करने की योजना बन रही है, तो यह समझ में आ जाता है कि उचित मूल्यांकन हो रहा है या नहीं।

मेरी राय है कि किसी कंपनी का स्वामित्व उसे कुशल या अक्षम नहीं बनाता। हर कंपनी में उसका प्रबंधन बड़ा मायने रखता है। आप लोग हमेशा निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना करते हैं। इसलिए, यदि आप बीपीसीएल और एस्सार की तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे कि बीपीसीएल की लाभप्रदता लगातार बढ़ रही है।

रिफाइनरी के संदर्भ में देखें तो एस्सार बीपीसीएल का केवल आधा है। एस्सार पेट्रोल स्टेशन नहीं चलाता है, लेकिन बीपीसीएल हजारों की संख्या में पेट्रोल स्टेशन संचालित करता है।

आपका मतलब है कि एक लाभदायक और पेशेवर रूप से चलाए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए?

यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। समस्या यह है कि, एस्सार, जो कि बीपीसीएल का आधा है, बीपीसीएल के मूल्य की तुलना में अब अधिक मूल्यवान है। क्या इसका मतलब यह है कि क्या बीपीसीएल को ठीक से महत्व दिया गया है?

तो, माना जाए कि आप बीपीसीएल में विनिवेश का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि बीपीसीएल में विनिवेश के तरीकों का विरोध कर रहे हैं?

हाँ। अगर उन्होंने इक्विटी रूट का पालन किया होता, तो इस तरह का मूल्यांकन नहीं होता। जब भी आप रणनीतिक

भागीदारों के साथ सौदे करते हैं, तो मूल्यांकन की समस्या पैदा होगी। और यहां तो केवल 2-3 खरीदार हैं।

तो, सवाल यह है कि जब आपके पास दूसरा रास्ता है, तो आप इसका प्रबंधन दूसरे के हाथों में क्यों देना चाहते हैं। जबकि इक्विटी रूट के जरिये विनिवेश आपको बहुत अच्छी रकम दिला सकता है।

अगर हम हिंदुस्तान जिंक के मामले को देखें, जो वर्ष 2002 में वाजपेयी के समय बेचा गया था, उसमें मुनाफा सौ गुना तक बढ़ गया। इसी तरह बालको, आईपीसीएल, आदि।

हां, हर कोई कहता है कि विनिवेश के बाद ये कंपनियां अधिक कुशल और लाभदायक बन गईं। हम सहमत नहीं हैं। 769 करोड़ रुपये (7.69 बिलियन रुपये) में हिंदुस्तान जिंक की बिक्री की गई थी, वह कीमत कम थी। आज की तारीख में इसे देखें, तो इस कंपनी का सिर्फ 30 प्रतिशत शेयर ही 30,000 करोड़ रुपये (300 अरब रुपये) के बराबर हैं।

क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का मुनाफा विनिवेश के बाद 100 गुना बढ़ गया?

यह केवल लाभ नहीं है, इसमें अन्य बातें भी हैं जैसे कि सरकार को राजस्व। मैं जो कह रहा हूँ, हमारे पास निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बहुत बुरे अनुभव हैं। जिस तरह से वे करों का भुगतान करते हैं, सभी प्रकार की रियायतें ले लेते हैं, वैसा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं कर पाती। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपना कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं करती।

तो, क्या आप भी निजीकरण के खिलाफ हैं?

आप सीधे निष्कर्ष पर जा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि जब आप एक निजी व्यावसायिक घराने को सार्वजनिक उपक्रम देते हैं, तो आप इसे घाटे में क्यों बेचना चाहते हैं?

मैं आपको सरकारी कंपनियों के कुछ उदाहरण दूंगा जो स्वतंत्र बोर्डों द्वारा चलाए जाते हैं। मसलन, एलएंडटी और आईटीसी को ही लें। दोनों सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन कुशलता से चलती हैं। मालिक सरकार है, लेकिन प्रबंधन सरकारी नहीं है।

लेकिन सरकारें कारोबार क्यों चला रही हैं?

सरकार को व्यवसाय नहीं चलाने चाहिए और ये सरकार द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। निजी इक्विटी होल्डिंग 51 प्रतिशत होने के कारण, नौकरशाही का नियंत्रण खत्म हो जाता है और कंपनियां स्वतंत्र बोर्डों द्वारा चलाई जाती हैं। अगर नौकरशाही का नियंत्रण नहीं होगा तो चीजों में सुधार होगा। समस्या नौकरशाही के नियंत्रण की है न कि कंपनी के स्वामित्व की।

राष्ट्रीय संपत्तियां, जो जनता की भावनाओं और कर-दाताओं के पैसे के माध्यम से वर्षों में बनाई जाती हैं,

उन्हें कम कीमत पर व्यावसायिक घरानों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। यदि आप बीपीसीएल जैसी कंपनियों को निजी क्षेत्र को बेचते हैं, तो उन्हें हमेशा कार्टेल बनाने की इच्छा होती है। हमने इसे पहले भी देखा है। जब कार्टेल बनाए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। हमने निजी घरों के कई मामलों में सार्वजनिक धन लुटते देखा है।

स्वामित्व आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाता है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि उसे किस तरह चलाया जाता है।

इसलिए, हमारा तर्क यह है कि बीपीसीएल को उचित रूप से महत्व दिया जाना चाहिए और इक्विटी मार्ग के माध्यम से बेचा जाना चाहिए।

सार्वजनिक भावनाओं और कर-दाताओं के पैसे से बनाई गई संपत्तियों के लिए सरकार को सर्वाधिक और उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। सरकार के रास्ते में नीति आयोग या अन्य सलाहकारों के आने का क्या मतलब?

जब वे अधिक कीमत प्राप्त कर सकते हैं तो हमें उन्हें कम कीमत पर विनिवेश के नाम पर क्यों बेचना चाहिए? इक्विटी रूट क्यों नहीं?

यदि रणनीतिक बिक्री पारदर्शी है और खरीदार भी अधिक हो तो...?

समस्या यही है कि यह पारदर्शी नहीं है। यदि सौ खरीदार हैं, तो यह पारदर्शी है। यहां आपके पास केवल दो या तीन खरीदार हैं और वे आपस में हाथ मिला लेते हैं और औने-पौने दामों पर राष्ट्रीय संपत्ति को हथिया लेते हैं।

सरकार इस पचड़े में ही क्यों पड़े? सरकार उस इक्विटी मार्ग से क्यों नहीं जा सकती, जिसका उसने पिछले पांच वर्षों में पालन किया था?

अब, मैं आपको एयर इंडिया के बारे में बताता हूँ। सलाहकारों की नजर में एयर इंडिया की संपत्ति बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में, एयर इंडिया ने लेंडिंग अधिकारों के लिए कई एयर स्लॉट का अधिग्रहण किया है और इन एयर स्लॉटों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है। जब सलाहकार कहते हैं कि एयर इंडिया का नकारात्मक मूल्य है, तो वे झूठ बोल रहे हैं। इन सलाहकारों ने हवाई स्लॉटों को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया है।

क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमने हीथ्रो में 400 करोड़ रुपये (4 बिलियन) में एक एयर स्लॉट बेचा है? और हमारे पास अकेले हीथ्रो और बर्मिंघम में 70 ऐसे एयर स्लॉट मौजूद हैं।

वर्तमान में हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2,500 से अधिक हवाई स्लॉट हैं। दुनिया भर में हवाई स्लॉट को किराए पर देने की एक अंतराष्ट्रीय प्रथा है। लेकिन परामर्श



कंपनी द्वारा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

लेकिन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पांच सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है ...

मैं कहूंगा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल और सरकार को सलाहकारों द्वारा गलत जानकारी दी गई है। इसीलिए, जब सरकार नकारात्मक मूल्य के साथ उन्हें बेचने जा रही है, तो उसके साथ ही सभी तरह के कर भी हटा रही हैं।

हमारा कहना है कि आप एक पेशेवर प्रबंधन द्वारा एयर इंडिया को क्यों नहीं चलाते हैं? इसे दुनिया भर में चलाईये। आप आईपीओ के साथ आकर खुदरा निवेशकों के हाथों एयर इंडिया को क्यों नहीं बेचते।

हमारे पास ब्रिटिश एयरवेज का एक उदाहरण मौजूद है। 1980 के दशक में, ब्रिटिश एयरवेज उसी आकार में था। 1987 में, इसे बदल दिया गया और एक आईपीओ जारी किया गया, जिसमें 11 गुणा ज्यादा आवेदन हुआ, इसे अब बहुत कुशलता से चलाया जा रहा है।

मेरा कहना है कि एयर इंडिया की हालत ठीक नहीं है तो उसका उपाय करिये। किसी का हाथ अस्वस्थ है तो उसे काटने का रवैया अच्छा नहीं है। पहले उसका इलाज होना चाहिए।

वर्तमान में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। जीडीपी की दर नीचे है और सरकार इसे ऊपर उठाने को बेताब है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु आवश्यक धन के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की कोशिश हो रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार को फंडिंग से कौन रोक रहा है? हम जो कह रहे हैं उसे इक्विटी रूट के माध्यम से बेचें ताकि उन्हें अधिक पैसा मिल सके!

हम चाहते हैं कि इन उपक्रमों को औने-पौने दाम में बेचने की वजाय सरकार को ज्यादा पैसा मिले।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और पैसा लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं।

हम हमेशा विदेशी सलाहकारों के आलोचक रहे हैं क्योंकि उनके निजी हितों का टकराव रहा है।

आपने खरीदारों को दिए गए अनुचित लाभ के बारे में बात की। यह क्या है?

सबसे पहले, हमें कार्टेल बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद ये जो हमारी रणनीतिक संपत्ति हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले आठ वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये (600 बिलियन रुपये) का लाभ कमाने वाली कंपनी का बहुसंख्यक हिस्सा 56,000 करोड़ रुपये (560 बिलियन रुपये) में बेचा जा रहा है।

विदेशी सलाहकार ही नहीं, नीति आयोग ने भी सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का आकलन किया है।

मुझे नीति आयोग की सिफारिशों पर कोई विश्वास नहीं है। वास्तव में, हमने नीति आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए कहा है। हालांकि नीति आयोग एक हिंदी नाम की तरह लगता है, लेकिन इसके अधिकांश सलाहकार विदेशी हैं।

आपने संप्रभु बांड, आरसीईपी और अब विनिवेश पर सरकार का विरोध किया। क्या स्वदेशी जागरण मंच सही मायने में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है?

नहीं, हम सरकार के मित्र हैं। हिंदी में एक कहावत है 'निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय'। ऐसा इसलिए ताकि जब कभी आप गलत हो तो आपको सुधारा जा सके। आप खुद संभल सके। हमने आरसीईपी का शुरु से विरोध किया। अब, हर कोई सरकार की सराहना कर रहा है क्योंकि उन्होंने आरसीईपी को स्वीकार नहीं किया है। तो, लाभार्थी कौन है? स्वदेशी जागरण मंच या सरकार?

हमने संप्रभु बांडों का विरोध किया और एक बहस शुरु की। अंततः सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया। किसको फायदा हुआ? देश का? सरकार का? या स्वदेशी जागरण मंच का?

स्वदेशी जागरण मंच एक मित्र है जो सरकार को सही तरीके से मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है ताकि पूरे देश को उसका लाभ मिल सके।

क्या स्वदेशी जागरण मंच वामपंथ के रास्ते पर जा रहा है?

स्वदेशी जागरण मंच वामपंथ नहीं है। वामपंथी कभी भी विनिवेश को स्वीकार नहीं करेंगे। तो, क्या हम वामपंथी हैं? हमारी सोच में कोई राइट या लेफ्ट नहीं है। एक आम धारणा है कि राइट का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉरपोरेट्स, वैश्वीकरण और बड़े बाजारों से है। अगर यह सही है, तो हमें राइट कहलाना पसंद नहीं है।

हम सिर्फ राष्ट्रवादी हैं। हर चीजों को देखने की हमारी राष्ट्रवादी दृष्टि है, न कि दक्षिणपंथी तरीका। □□

सब काम रोबोट से होगा, तो इंसान क्या करेगा?

भारत में आबादी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मशीनीकरण का काम भी बढ़ रहा है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बोलबाला बढ़ा है। बढ़ती आबादी के चलते देश में बेरोजगारी की संख्या में भी गुणात्मक गति से इजाफा हुआ है। आंकड़ों के जरिये बताया जा रहा है कि फिलवक्त बेरोजगारी की दर अपने चरम पर है। ऐसे में मशीनीकरण की यह आंधी ही हमें बेरोजगारी की अंधी सुरंग की ओर तो नहीं धकेल रही है। यह लाजिमी सवाल है, लेकिन सरकार तथा सरकार के संतुलनकार इससे आंखें बंद किये हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट भी इस बात का समर्थन करती है कि रोबोट के कारण विकासशील देशों के 70 प्रतिशत रोजगार समाप्त हो सकते हैं।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक आबादी पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2027 तक भारत की आबादी दुनिया में सर्वाधिक होकर डेढ़ अरब के पार चली जायेगी। अभी भारत की आबादी 137 करोड़ के आसपास है। जबकि पड़ोसी चीन की आबादी 143 करोड़ है। जाहिर है कि आबादी वृद्धि की मौजूदा रफ्तार कायम रही तो हम इस मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही भारत के समक्ष गरीबी, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण आदि का भारी दबाव होगा। इस दबाव को कम करने के लिए हमें न्याय संगत नीतियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। लेकिन लाख टके का सवाल है कि दुनिया के सुर में सुर मिलाते हुए मशीन की तरफ बढ़ने से क्या रोजगार के अवसर में कमी नहीं होगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि मशीन किसी भी उद्योग व्यापार के लिए एक लाभकारी साधन है। जो काम 10-20 मनुष्य नहीं कर सकते, वह काम बिना थके, बिना रुके एक मशीन से किया जा सकता है। यही कारण है कि मशीन और मनुष्य का रगड़ा प्रारंभ से ही रहा है। पूर्व में भी तरक्की के वास्ते मशीन को आवश्यक बताते हुए संतुलनकारों ने रोजगार के साथ सामंजस्य



आबादी बढ़ने के साथ ही भारत के समक्ष गरीबी, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण आदि का भारी दबाव होगा। इस दबाव को कम करने के लिए हमें न्याय संगत नीतियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी।
— अनिल तिवारी



बिटाने की कोशिश की। आज भी वह कोशिश कमोवेश जारी है। केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार 'कौशल विकास' के जरिये लोगों को कुशल बनाने में लगी हुई है। सरकार का मानना है कि अत्याधिक कुशलता प्राप्त करने के बाद लोगों को कुशल रोजगार प्राप्त हो सकता है। बीते पांच सालों में लगभग चार करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम के जरिये प्रशिक्षित किया जा चुका है।

हाल के दिनों में रोजगार कम होने की खबर है। ऐसे में इन प्रशिक्षित लोगों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार स्टार्ट-अप जैसी कई एक जमीनी योजनाएं शुरू कर प्रशिक्षित लोगों को आगे बढ़ाने की पहल कर रही है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थिति के चलते अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है। इसका विश्लेषण करने पर यूं तो कई एक चीजें उभरकर आ रही हैं, पर सबसे अधिक डराने वाली बात वैश्विक प्रभाव और उद्योगों में रोबोट का उपयोग शामिल है।

वैश्वीकरण के प्रभाव में आज आर्थिकी के क्षेत्र में सबकी सोंच निवेश बढ़ाने और कार्पोरेट को सहारा देने की हो रही है। पहले ऐसी एकरूपता नहीं थी। राजनैतिक दलों के बीच भी उनके आर्थिक विचारों में फर्क साफ-साफ देखा जा सकता था। 60-70 के दशक तक का समय याद करें तो चीजें स्पष्ट थीं। नेहरू सरकारी और निजी क्षेत्र को साथ-साथ चलाने तथा सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की सोंच रखते थे, तो डॉ. लोहिया पूंजी के समाजीकरण को बढ़ावा देने तथा लोगों की आमदनी में अंतर को कम करने की बात करते थे। नेहरू अगर बड़े उद्योगों के पक्ष में थे, तो लोहिया छोटे और मझौले उद्योगों पर जोर देते थे। देश की राजनीति में नये आर्थिक विचार लाने का श्रेय गांधी को जाता है। गांधी ने मशीनीकरण और उपभोग पर आधारित अर्थतंत्र के

रोबोट विकासशील देशों का 70 प्रतिशत रोजगार खत्म कर सकता है। हम इस पर भी विचार करने को तैयार नहीं हैं कि भारतीयों को अभी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले आईटी सेक्टर पर इसका क्या असर होगा।

विकास का एक विकल्प सामने रखा। उन्होंने चरखा जैसे कार्यक्रमों के जरिये उसका ठोस रूप भी प्रस्तुत किया। बाद में ऐसे विकल्पों के प्रति खुलापन भारतीय राजनीति का चरित्र बन गया। स्वदेशी जागरण मंच प्रारंभ से ही इस विचार का कड़ा समर्थक रहा है कि भारत के लघु और मध्यम कारोबार को हर हाल में खुशहाल रखने की नीति शासन सत्ता को बनानी चाहिए ताकि आम भारतीयों के हित सुरक्षित रहें।

उदारीकरण की अर्थव्यवस्था के आने के बाद विचारों की यह विविधता समाप्त सी हो गई है। अब आर्थिक नीतियां तय करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी अनेक संस्थाओं का अहम योगदान रहता है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो हर कोई दुनिया की शीर्ष संस्थाओं को देखें बिना आगे बढ़ना नहीं चाहता। बैंकों के विलय और सरकारी कंपनियों के निजीकरण तथा आये दिन रणनीतिक बिक्री की बनने वाली योजना में कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है। अगर ठीक से गौर करें तो आर्थिकी एकरूपता अब केवल राजनीतिक दलों में ही नहीं कमोवेश आर्थिक और बौद्धिक जगत में भी पैठ बना ली है। हर विशेषज्ञ एक ही नजरिये से सोंचता हुआ दिखाई देता है तथा लगता है कि वैश्विक स्तर पर योजनाओं की भी लाबिंग की जा रही है।

उदारीकरण के तीस साल हो चुके हैं। क्या वह समय नहीं आ गया है कि इस पर सवाल उठाये जाएं। यह कितना न्याय संगत है कि देश की 58 प्रतिशत संपत्ति 1 प्रतिशत लोगों के पास चली गई है। देश के बीमारू राज्य और अर्द्धिक बीमार क्यों हो रहे हैं। पिछड़े और विकसित राज्यों के बीच का अंतर दिन-प्रति-दिन और अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है। गुजरात जैसे विकसित राज्य मानव विकास सूचकांक के मानकों पर केरल से पीछे क्यों हैं।

हालत यह है कि हम वैकल्पिक अर्थतंत्र के बारे में शायद सोचना ही नहीं चाहते। दुनिया भर में विषमता कम करने को लेकर थॉमस पिकेटी जैसे अर्थशास्त्रियों की राय पर हम ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस यानि रोबोट की जगह आदमी को प्राथमिकता देने की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की राय के प्रति भी बेपरवाह हैं। आईएलओ के मुताबिक रोबोट विकासशील देशों का 70 प्रतिशत रोजगार खत्म कर सकता है। हम इस पर भी विचार करने को तैयार नहीं हैं कि भारतीयों को अभी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले आईटी सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। हम जानते हैं कि मशीन ने पहले खेतीबाड़ी फिर निर्माण उद्योग आदि से भारी संख्या में रोजगार छिन लिया है।

63 साल पहले सिनेमा के रूपहले पर्दे पर आई फिल्म नया दौर में मशीन बनाम मनुष्य के झगड़े को बड़ी बारीकी से उकेरा गया था। फिल्म में तांगे के रोजगार से जुड़े समूह के मुखिया के तौर पर नायक की भूमिका अदा कर रहे दिलीप कुमार का वह संवाद आज भी शिद्दत के साथ याद किया जाता है 'कुंदन बाबू क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता जिससे देश की तरक्की भी हो, मालिकों को मुनाफा भी हो और मजदूरों की रोटी भी चलती रहे'।

मंदी से उबरने का एक नुस्खा यह भी

भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छंटते नहीं दिख रहे हैं। तमाम संस्थाओं का अनुमान है कि वर्तमान आर्थिक विकास दर चार से पांच प्रतिशत के बीच रहेगी जो कि पूर्व के सात प्रतिशत से बहुत नीचे है। इस परिस्थिति में कुछ मौलिक कदम उठाने पड़ेंगे अन्यथा परिस्थिति बिगड़ती जायेगी। पहला कदम सरकारी बैंकों की स्थिति को लेकर है। सरकार ने हाल में कुछ छोटे सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय किया है। साथ-साथ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी बैंकों की पूँजी में 250 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश के बावजूद समस्त सरकारी बैंकों के शेयरों की बाजार में कीमत, जिसे “मार्केट कैपिटलाइजेशन” कहते हैं, कुल 230 हजार करोड़ रुपये है। इसका अर्थ हुआ कि सरकार ने जो 250 हजार करोड़ रुपये इनमें निवेश किये उसमें से केवल 230 हजार करोड़ रुपये बचे है। इन बैंकों में पिछले चालीस वर्षों में जो देश ने निवेश किया है वह भी पूरी तरह स्वाहा हो गया है। यानि सरकारी बैंक अपनी पूँजी को उड़ाते जा रहे हैं और सरकार इन्हें जीवित रखने के लिए इनमें पूँजी निवेश करती जा रही है। इस समस्या का हल सरकारी बैंकों के विलय से नहीं निकल सकता है क्योंकि जिन सुदृढ़ बैंकों में कमजोर बैंकों का विलय किया गया है उनकी स्वयं की हालत खस्ता है। वे अपनी पूँजी को भी नहीं बचा पा रहे हैं। जब वे अपनी पूँजी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो वे कमजोर और छोटे बैंकों की पूँजी की कैसे रक्षा करेंगे, यह समझ के बाहर है। अतः सरकार को चाहिए कि इन बीमार बैंकों को जीवित रखने के स्थान पर इनका तत्काल निजीकरण कर दे। इनमें और पूँजी डालने के स्थान पर इनकी बिक्री करके 230 हजार करोड़ की रकम वसूल करे जिसका उपयोग देश की अन्य जरूरी कार्यों जैसे रिसर्च इत्यादि में निवेश किया जा सके।

सरकार ने बीते पांच वर्षों में वित्तीय घाटे में नियंत्रण करने में सफलता पाई है। 2014 में सरकार का वित्तीय घाटा हमारी आय का 4.4 प्रतिशत था जो 2019 में घटकर 3.4



सरकार ने बीते पांच वर्षों
में वित्तीय घाटे में
नियंत्रण करने में
I Qyrki lbZg 2014
में सरकार का वित्तीय
घाटा हमारी आय का
4.4 प्रतिशत था जो
2019 में घटकर 3.4
प्रतिशत हो गया है।
वित्तीय घाटे पर नियंत्रण
के लिए सरकार को
बधाई।
— डॉ. भरत झुनझुनवाला



प्रतिशत हो गया है। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के लिए सरकार को बधाई, क्योंकि यह दर्शाता है कि सरकार फिजूलखर्ची करने के लिए भारी मात्रा में बाजार से ऋण नहीं उठा रही है। लेकिन वित्तीय घाटे में जो कटौती हासिल की गयी है उसमें 3/4 हिस्सा पूँजी खर्चों में कटौती से हासिल किया गया है और केवल 1/4 हिस्सा चालू खर्चों में कटौती से हासिल करके किया गया है। पूँजी खर्च में कटौती से घरेलू निवेश कम हो रहा है। स्पष्ट है कि वित्तीय घाटे में नियंत्रण करने से न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न घरेलू निवेश बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में घरेलू मांग को बढ़ाने के उपाय करने होंगे। उपाय है कि मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता के हाथ में रकम पहुंचाने वाले सरकारी कार्यक्रमों में खर्च बढ़ाया जाये। जैसे सड़क बनाने के लिए जेसीबी के स्थान पर श्रम का उपयोग किया जाये। अथवा जंगल लगाने के लिए श्रमिकों को रोजगार दिया जाये। इस प्रकार के कार्य करने से आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति आएगी, वह बाजार से माल खरीदेगा और घरेलू बाजार की सुस्ती टूटेगी। इस खर्च को बढ़ाने के लिए सरकार को ऋण लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस कार्य के लिए वित्तीय घाटे को बढ़ने देना चाहिए। निवेश के लिए वित्तीय घाटे को बढ़ने देने में कोई खराबी नहीं है, उसी प्रकार जैसे अच्छा उद्यमी नयी फैक्ट्री लगाने के लिए बैंकों से ऋण लेकर निवेश करता है।

छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार ने बीते दिनों में कुछ सार्थक कदम उठाये हैं। जीएसटी में छोटे उद्योगों को रिटर्न फाइल करने में छूट दी गयी है और सरकारी बैंकों पर दबाव डाला गया है कि वे छोटे उद्योगों को भारी मात्रा में ऋण दें। फिर भी छोटे उद्योग



छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए सरकार ने बीते दिनों में कुछ सार्थक कदम उठाये हैं। जीएसटी में छोटे उद्योगों को रिटर्न फाइल करने में छूट दी गयी है और सरकारी बैंकों पर दबाव डाला गया है कि वे छोटे उद्योगों को भारी मात्रा में ऋण दें।

पनप नहीं रहे हैं। मूल कारण यह है कि चीन से भारी मात्रा में माल का आयात हो रहा है और उसके सामने हमारे उद्योग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चीन के माल के सस्ते आयात के पीछे चीन की दो संस्थागत विशेषताएं हैं। एक यह कि श्रमिकों की उत्पादकता वहां अधिक है। चीन के श्रमिकों को भारत की तुलना में ढाई गुना वेतन मिलता है लेकिन वे ढाई गुना से ज्यादा उत्पादन करते हैं। मान लीजिये उन्हें ढाई गुना वेतन मिलता है तो वे पांच गुना उत्पादन करते हैं। इस प्रकार चीन में माल के उत्पादन में श्रम की लागत कम हो जाती है।

चीन में श्रमिक के उत्पादकता अधिक होने का मूल कारण यह है कि वहां पर ट्रेड यूनियन और श्रम कानून ढीले हैं अथवा उद्यमी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। इससे उद्यमी द्वारा श्रमकों से जमकर काम लिया जाता है और माल सस्ता बनता है। चीन में माल सस्ता होने का दूसरा कारण भ्रष्टाचार का स्वरूप है। चीन में भी नौकरशाही उतनी ही भ्रष्ट है जितनी की अपने देश में। चीन से व्यापार करने वाले एक उद्यमी ने बताया कि किसी चीनी उद्यमी को नोटिस दिया गया कि उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा क्योंकि वहां से सड़क बननी है। इसके बाद चीनी सरकार के अधिकारी उद्यमी के दफ्तर पहुंचे और उससे साफ-साफ

बातचीत हुई। उद्यमी ने कहा कि उसे अपनी फैक्ट्री को अन्य स्थान में ले जाने में वर्तमान की तुलना में तीस प्रतिशत खर्च पड़ेगा। अधिकारियों ने उसी स्थान पर तीस प्रतिशत अधिक रकम का चेक दे दिया और छः महीने में उसने अपनी फैक्ट्री को दूसरी जगह लगा दिया। उस स्थान पर सड़क का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया में चीन के अधिकारियों ने घूस भी खाई। लेकिन अंतर इस बात का है कि मामला आंतरिक वार्तालाप से तय हो गया। सड़क भी शीघ्र बन गयी और उद्यमी भी परेशान नहीं हुआ। इस प्रकार जो विवादित मामले हैं उनको सामने-सामने बैठकर हल कर लिया जाता है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत कम पड़ती है।

लेकिन श्रम कानून और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना भारत के लिए एक कठिन कार्य है। इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि चीन से आयातित होने वाले माल पर आयात कर बढ़ाए और यदि जरूरत हो तो इस कार्य को करने में विश्व व्यापार संगठन के बाहर भी आ जाए। क्योंकि अपने देश की जनता के रोजगार की रक्षा करना प्राथमिक है। सरकार को गंभीरता से मौलिक कदम उठाने चाहिए अन्यथा अर्थव्यवस्था की गति बिगड़ते ही जाने की संभावना बनती ही जा रही है। □□

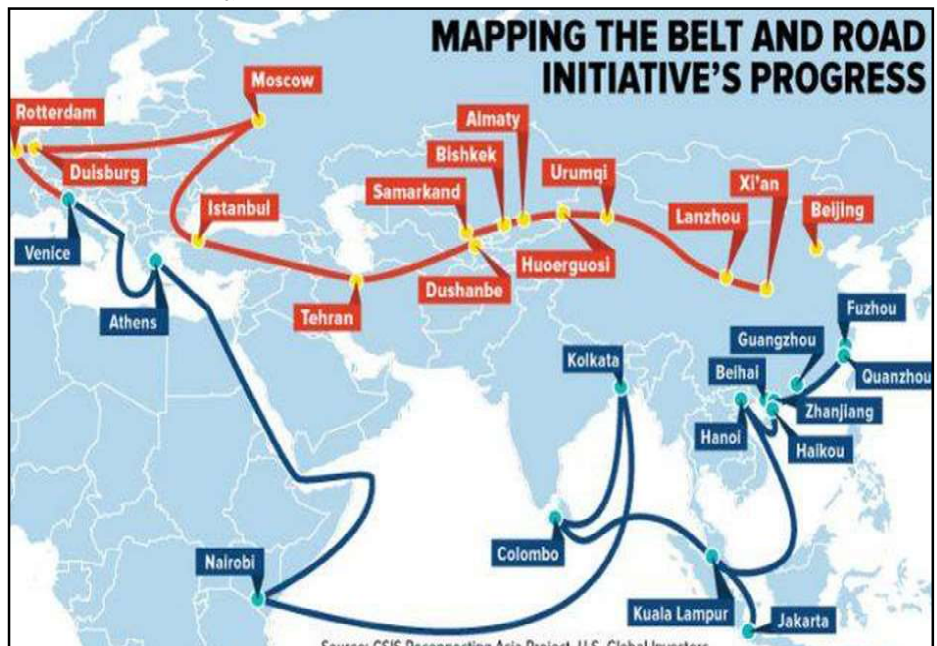
बेल्ट रोड के रास्ते विस्तारवाद को अंजाम देता चीन

श्रीलंका के 'हंबनटोटा' बंदरगाह पर कब्जे को पुनः याद करवाते हुए, चीन केन्या के अत्यंत लाभकारी 'मुंबासा' बंदरगाह पर भी काबिज होने जा रहा है। गौरतलब है कि केन्या के रेलवे के विकास हेतु चीन ने भारी मात्रा में उधार दिया हुआ है। चीन जल्द ही अपने ऋण की अदायगी न होने के कारण यह कार्यवाही करने जा रहा है। यही नहीं नैरोबी स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी चीन द्वारा अधिग्रहण के खतरे में है।

याद रखना होगा कि लगभग इसी प्रकार की कार्यवाही श्रीलंका के साथ भी की गई थी, जब श्रीलंका को चीनी उधार न चुका पाने के कारण 'हंबनटोटा' बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पर चीन को सौंपना पड़ा था। लगभग हंबनटोटा की तर्ज पर ही केन्या का मुंबासा बंदरगाह भी चीन के कब्जे में जाने वाला है। गौरतलब है कि चीन ने केन्या की रेलवे परियोजना एसजीआर के निर्माण हेतु 550 अरब केन्यायी शिलिंग उधार दी हुई हैं और चूंकि इस परियोजना से पर्याप्त प्राप्ति नहीं हो पा रही और पहले ही साल उसमें 10 अरब केन्यायी शिलिंग का नुकसान हुआ है। चीन उस परियोजना को ही नहीं बल्कि उस परियोजना के घाटे की भरपाई के लिए उसके मुंबासा बंदरगाह को भी अधिग्रहित करने जा रहा है। केन्या के ऑडिटर जनरल का कहना है कि चीन के एक्विजि बैंक के साथ एकतरफा समझौता हुआ, और यहां तक कि इस समझौते की मध्यस्थता भी चीन में ही हो सकती है। गौरतलब है कि अभी भी एसजीआर की सभी प्राप्तियां चीन के कब्जे वाले समझौते के अनुसार एसक्रो खाते में ही जाती है।

इस समझौते की सबसे खतरनाक धारा यह है कि केन्या सरकार ने चीन को न्यूनतम व्यवसाय की गारंटी दी हुई है। इस प्रकार चीन के साथ हुए इस खतरनाक समझौते के कारण अब केन्या की महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिसंपत्तियां चीन के कब्जे में जाने को तैयार है।

आगे आने वाला समय
बातएगा कि क्या चीन
स्वयं की 'एकला चलो'
नीति से बाहर आकर
बीआरआई को वैश्विक
मंचों के माध्यम से आगे
बढ़ाने के लिए विस्तृत
प्रयास करेगा अथवा
उस पर आ रही
आशंकाओं को सही
सिद्ध करते हुए अपनी
उसी संकीर्ण मानसिकता
में रहकर स्वयं अपनी
ही योजना में बाधाएं
खड़ी कर देगा।
— स्वदेशी संवाद



बेल्ट रोड योजना या कर्जजाल की कूटनीति

गौरतलब है कि बीआरआई को एक वृहत इन्फ्रास्ट्रक्चर पहल कहा जा रहा है, जिसके अनुसार सड़क, रेल और समुद्री मार्गों को विकसित करते हुए दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आवाजाही में सुधार किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। इस प्रस्ताव को 'ऐतिहासिक सिल्क रोड' की अवधारणा से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पूरे होने से विभिन्न मुल्कों के बीच सड़क, रेल और जल मार्ग की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी, जिससे सामान की आवाजाही आसान और सस्ती होगी, साथ ही साथ इससे समय की भी बचत होगी।

चीन यह तर्क दुनिया के गले उतारने की कोशिश कर रहा है कि बीआरआई पहल विकासशील देशों को आपसी व्यापार, आर्थिक लेनदेन और संपर्क बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी। बीआरआई के फायदों के बारे में बताते हुए सार्वजनिक चर्चाओं में कोशिश यह हो रही है कि इसके राजनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक खतरों को छुपाया जाए।

किसी भी योजना की सफलता उसके वित्तीयन पर निर्भर करती है। यह बात इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ज्यादा लागू होती है। जब बेल्ट रोड परियोजना की शुरुआत हुई तो वित्तीयन का सारा दारोमदार चीन सरकार, चीन के नेतृत्व वाले एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक और चीन की दूसरी संस्थाओं पर ही रहा।

वास्तव में हुआ यह कि चीन की वित्तीयन व्यवस्था में चीन सरकार द्वारा स्वयं अथवा चीनी सरकार के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण, कई देश कर्ज के जाल में फंस गये। इस बाबत श्रीलंका एक बड़ा उदाहरण बना। श्रीलंका के हाल को देख कई देशों ने चीन के



चीन यह तर्क दुनिया के गले उतारने की कोशिश कर रहा है कि बीआरआई पहल विकासशील देशों को आपसी व्यापार, आर्थिक लेनदेन और संपर्क बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों से किनारा करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि दो साल पहले एक अरब डालर के कर्ज के असहनीय बोझ के चलते श्रीलंका को अपना एक बंदरगाह खोना पड़ा। इसी प्रकार जिबाऊटी, जो अफ्रीका में अमरीका का मुख्य सैन्य अड्डा रहा है, में एक और बंदरगाह भारी कर्ज के चलते, अब चीन की एक कंपनी के नियंत्रण में जाने की कगार पर है। देशों के बढ़ते कर्जजाल के कारण बीआरआई का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। पिछले दो सालों में बीआरआई भागीदार देशों में विपक्षी दल ही नहीं सामाजिक संस्थाएं भी बीआरआई का जमकर विरोध कर रही हैं।

पाकिस्तान का अनुभव?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) बीआरआई की पहली परियोजना बताई जाती है। उसका अनुभव भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शक माना जाना चाहिए। चार वर्ष पहले जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि सीपीईसी पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित होगा। लेकिन चार साल के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान कर्ज में डूब गया है, सरकारी राजस्व नहीं बढ़ रहा है और वहां की ग्रोथ 2017-18 में 5.8 प्रतिशत से घटती हुई 2018-19 में 3.4 प्रतिशत पहुंच गई है और जिसके 2019-20 में 2.7 प्रतिशत हो जाने की आशंका है, पाकिस्तान में

कोई भी यह नहीं कह रहा है कि सीपीईसी 'गेम चेंजर' है।

पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाई जा रही इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भारी लागत के चलते पाकिस्तान पर ऋण का बोझ तो बढ़ रहा है और अदायगी का दबाव भी, लेकिन इन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से लाभ बहुत अनिश्चित हैं। इसलिए पाकिस्तान सीपीईसी परियोजना से बहुत आशावित नहीं है।

समझना होगा कि विश्व बैंक को भी बीआरआई योजना के संदर्भ में बहुत सी आशंकाएं हैं। विश्व बैंक की कई रपटों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बीआरआई परियोजना को अपने हाथ में लेकर बढ़ाने के प्रयासों की कमी है। चीन के तमाम प्रकार के विरोधाभास और चीन की स्पष्ट विस्तारवादी नीति इस समस्या के समाधान में रोड़ा बन सकते हैं। आगे आने वाला समय बातेंगा कि क्या चीन स्वयं की 'एकला चलो' नीति से बाहर आकर बीआरआई को वैश्विक मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत प्रयास करेगा अथवा उस पर आ रही आशंकाओं को सही सिद्ध करते हुए अपनी उसी संकीर्ण मानसिकता में रहकर स्वयं अपनी ही योजना में बाधाएं खड़ी कर देगा। लेकिन कुछ भी हो, अभी तो कम से कम दस देश चीन की कर्जजाल नीति का शिकार होकर भारी नुकसान में हैं। □□

आर्थिक सुस्ती है, मंदी नहीं

भारत में अराजनीतिक अर्थ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इस समय आर्थिक सुस्ती की स्थिति है न कि मंदी की, जिसको लेकर भारत का आर्थिक विकास रुका नहीं है। आर्थिक विकास की गति कुछ समय के लिए कम हो सकती है, परन्तु थोड़े ही समय में यह पुरानी रफ्तार जरूर पकड़ लेगी। इसका कारण कई-कई घटकों पर निर्भर करता है जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं।

कांग्रेस के भारत के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम् जेल में रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिन्ताग्रस्त है। उन्होंने मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए दोषी ठहराते हुए कहा है कि सरकार उचित आलोचना को भी स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन को सामने लाना चाहिए। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार को सब पता है लेकिन वह उचित आलोचना तथा उचित सलाह को मानने से इंकार करती है।

पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह ने समाचार पत्र में लिखे अपने एक लेख में कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण डर व अविश्वास का माहौल है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है। भारत के नागरिक व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते डॉ. मनमोहन सिंह लिखते हैं कि गत 15 वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सबसे निचले दर पर है, बेरोजगारी गत 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर है, लोगों की खर्च करने की क्षमता गत 40 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है, बिजली उत्पादन की वृद्धि दर गत 15 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है तथा बैंकों का बैड लोन सबसे उच्चतम स्तर पर है। डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार यह उच्चतम व न्यूनतम की सूची बहुत लंबी है और निराश करने वाली है। अब तो इन आंकड़ों के प्रकाशन पर भी पहरा लगा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके समाज की कार्य प्रणाली को दर्शाती है। कोई भी अर्थव्यवस्था



गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में सरकार का पूरा ध्यान शिक्षा व स्वास्थ्य पर होना चाहिए क्योंकि किसी भी देश में गरीबी घटाने, अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि को लाने में इन दोनों पहलुओं की सबसे अहम भूमिका होती है।
— डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल



लोगों व संस्थाओं की भागीदारी से चलती है। आर्थिक वृद्धि का मूल तत्व पारस्परिक भरोसा और आत्मविश्वास होता है परंतु आज सामाजिक विश्वास की बनावट और भरोसे को संदिग्ध बना दिया गया है। बैंक उद्योगपतियों को नया कर्ज देने से डर रहे हैं। उद्यमी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से डर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप, आर्थिक वृद्धि दर और नौकरियां विकास के नए इंजन हैं, लेकिन इन सब में निराशा का वातावरण है। अविश्वास के इस माहौल में अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती है। संस्थानों व लोगों के बीच अविश्वास बढ़ेगा तो इससे अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित होगी ही। भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार हर चीज को और हर किसी को शक की नजर से देख रही है, क्योंकि मोदी सरकार यह मानती है कि ऐसी स्थिति पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों व गलत इरादों से बनी थी। भारत की तीन अरब डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिसे मनमाने ढंग से निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

डॉ. मनमोहन के इस लेख को भाजपा ने कांग्रेस का सदाबहार प्रलाप बताया है। लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं है। उद्योगों को कर में राहत दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी सुविधाएं दी गई हैं। कई बैंकों को बड़े बैंकों के साथ संविलयन कर दिया गया है जिसका उद्देश्य बैंकों को शक्तिशाली करना है। जीएसटी व नोटबंदी से करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। सरकार ने काले धन के विरुद्ध कदम उठाये हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार 2014 से 2019 तक औसत रूप से जीडीपी वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है। जो जी-20 देशों में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर की वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार विश्व भर में आर्थिक सुस्ती है, जीडीपी

वर्तमान आर्थिक सुस्ती वैश्विक आर्थिक संकट शुरू होने के कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि 2011 के आते-आते विश्व की अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरनी प्रारंभ हो गई थी।

वृद्धि दर में कमी आयी है। इसके बाबजूद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकास कर रही है। देश में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश करने लायक माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकार ने मंहगाई को नियंत्रित किया है तथा सरकारी नीतियों को उदार बनाया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटा कर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। घरेलू उद्योग का टैक्स 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है। यह विश्व में सबसे कम है। 2020 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार हुआ है।

वर्तमान आर्थिक सुस्ती वैश्विक आर्थिक संकट शुरू होने के कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि 2011 के आते-आते विश्व की अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरनी प्रारंभ हो गई थी। कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही थी जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इस गिरती स्थिति को संभालने के लिए घरेलू स्तर पर राहत पैकेज दिये गये, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिली। परन्तु पैकेज वापस लेने पर समस्याएं पुनः उत्पन्न होने लगी। अर्थव्यवस्था की मंदी की स्थिति को सुधारने के लिए लोगों की खपत (खर्च), निजी निवेश, निर्यात और सरकार के खर्च पर ध्यान दिया जाता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में

2011-2018 के बीच वास्तविक वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इस अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 22 लाख नौकरियां सृजित हो रही थी। बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि 2004-05 में प्रतिवर्ष 75 लाख नौकरियां सृजित हो रही थी। जब लोगों की आमदनी कम होती है तो खर्च में भी स्वतः कमी हो जाती है। जिससे मांग कम हो जाती है और मंदी आने लगती है और कारखानों के स्टॉक में बिना बिका माल अधिक हो जाता है। मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र तथा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी नौकरियां कम हो गई। इन क्षेत्रों में गांवों से शहर आकर लोग काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में भी नौकरियां बढ़ने की दर कम होकर 13.4 प्रतिशत हो गई। जब वेतन व आय कम होती है तो बचत भी कम हो जाती है जिससे सकल घरेलू बचत में भी कमी आ जाती है। इससे पूंजी निर्माण भी कम हो जाता है।

निजी कंपनियों की बचत दर 2017-18 में 11.6 प्रतिशत हो गई, परंतु उनकी निवेश की मांग उतनी नहीं बढ़ी। 2017-18 में जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 11.6 प्रतिशत थी जो कि 2013-14 में 17.2 प्रतिशत थी। सरकार के द्वारा व्यय करने से भी मांग बढ़ती है। राजकोषीय संकट के कारण पूंजीगत खर्च कम हो जाते हैं। सरकार घाटा नियंत्रित भी करना चाहती है। ऐसे में वित्तीय बचत की रकम निजी क्षेत्र को निवेश के लिए नहीं मिल पाती है। वैश्विक आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए मनरेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बुनियादी ढांचे पर खर्च से आर्थिक संकट का मुकाबला करने की कोशिश की गई। परंतु 2008 की कर्ज माफी योजना वैश्विक आर्थिक संकट से मुकाबला करना भारी पड़ गया। विभिन्न राहत पैकेज दिये गये जिससे मंहगाई बढ़ गई। मंहगाई को नियंत्रित करने की रिजर्व बैंक की नीति के कारण विकास दर पर

नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। 2008 के आर्थिक संकट के बाद ऋण अधिक दिये गये जिससे बैंक एनपीए संकट का सामना कर रहे हैं। कम ऋण वितरण का मूल कारण अधिक एनपीए है।

आरबीआई को रेपो रेट कम करके उसका लाभ शीघ्र ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्यात बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी कम कर देनी चाहिए। सरकार को आय बढ़ाने के लिए सरकारी उपक्रमों की बेकार पड़ी संपत्तियों व जमीनों को बेच देना चाहिए। भारत को कम से कम 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करनी ही चाहिए तभी भारत की अर्थव्यवस्था पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकेगी। बुनियादी आर्थिक सुधार किये जा सकते हैं। औद्योगिक नीतियों में बदलाव भी होना चाहिए। लंबित पड़ी विकास योजनाओं को भी शीघ्र पूरा किया जाये एवं केन्द्र व राज्यों में खाली पड़े सरकारी

व निजी संस्थाओं में पड़े पदों को नौकरियां देकर भरा जाये।

अंधाधुंध ऋण बांटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के प्रयास प्रत्येक स्तर पर होने चाहिए। उद्योग-व्यापार की परेशानी का मुख्य कारण आर्थिक मंदी है। बेरोजगारी की दर को कम से कम करने के प्रयास होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और विश्व के सबसे बड़े धनपति बिल गेट्स को विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पास बेहद तेज गति से विकास करने की पूरी क्षमता है। आगामी एक दशक में भारत की विकास गति इतनी तेज होगी कि लोग गरीबी से उबर सकेंगे और सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं में बड़ा निवेश कर सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी को आशा है कि भारत सचमुच तेज विकास दर हासिल करेगा। इसकी वजह यह है कि भारत

के पास भरपूर क्षमता है।

गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में सरकार का पूरा ध्यान शिक्षा व स्वास्थ्य पर होना चाहिए क्योंकि किसी भी देश में गरीबी घटाने, अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि को लाने में इन दोनों पहलुओं की सबसे अहम भूमिका होती है। इस वर्ष गत वर्षों की तुलना में बेहतर बरसात हुई है। देश के अधिकांश जलाशय 90 प्रतिशत तक लबालव भरे हुए हैं। अन्य जल स्रोत भी लबालव हैं तथा भूजल स्तर में भी सुधार है। इस सबसे आगामी फसलें बहुत अच्छी हो सकती हैं। जिससे कृषि उपजों की उपलब्धता अधिक रहेगी। यह सब देश की अर्थव्यवस्था में चल रही सुस्ती को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। आर्थिक कमजोरी का हल कॉरपोरेट जगत तथा स्टॉक मार्केट को पैकेज देने से नहीं अपितु किसान व कृषि पर ध्यान देने से हो सकता है। □□

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय गुजपकरनगर 251001 (उ.प्र.) के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार हैं।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि 'स्वदेशी पत्रिका' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/- रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/- रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22

अधिक जानकारी के लिए देखें :

**http://
swadeshionline.in/**

निर्मलता, अविरलता, गंगत्व के लिए

गंगा को चाहिए एक और भगीरथ

गंगा मात्र नदी नहीं, अपितु भारतीय समाज के लिए वह गंगा मां है। गंगा को गंगा बनाने वाला न तो उसमें जल है और न ही भारतीय संस्कृति को अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत। वह नित्य प्रति निरंतर सूखती जा रही है। गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक उसमें प्रवाहित होने वाला कलुषित जल श्रद्धालुओं के लिए भले ही जल हो, किंतु आम आदमी उसे जल के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सौभाग्य से वर्ष 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रत्याशी बने और उन्होंने अपने आप को गंगा के पुत्र के रूप में प्रस्तुत कर गंगा के आवाहन पर बनारस आने तथा गंगा को प्रदूषण मुक्त कर उसे अविरल प्रवाह प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। चुनावी सफलता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर, अपनी चुनावी घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए उसे मूर्त रूप देने के लिए नमामि गंगे नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर गंगा की मुक्ति, शुद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

वस्तुतः नमामि गंगे परियोजना का लक्ष्य गंगा को बचाना है, उसे प्रदूषण से मुक्ति प्रदान करना तथा गंगा के प्रवाह को उसके मौलिक स्वरूप में लाना है। इस योजना का आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना अर्थात् स्वच्छ गंगा परियोजना है। इस परियोजना हेतु वर्ष 2014-15 के बजट में 2037 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि की व्यवस्था कर योजना को प्रारंभ किया गया था।

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना के नाम से प्रारंभ हुआ था जिसके द्वारा दूषित कचरा एवं मल-जल लेकर गंगा में मिलने वाले नालों की पहचान कर उन पर जल उपचार संयंत्र लगाने की योजना प्रारंभ की गई थी और मार्च 2000 में लगभग 451 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद इस योजना को पूर्ण घोषित कर दिया



जल संवर्धन एवं जल संरक्षण ही नदियों के जलस्तर में वृद्धि कर उन्हें गति दे सकता है जो आम जनमानस के सहयोग से ही संभव है।
— डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र



गया था किंतु अब तक किए गए कार्य से कोई सार्थक परिणाम उपस्थित नहीं हुआ। सरकार ने 16 राज्यों में 34 नदियों की सफाई के लिए 5800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और अपने हिस्से की 2500 करोड़ की धनराशि भी विभिन्न राज्यों को प्रदान किया था, जिससे गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों की भी साफ-सफाई हो सके। इन नदियों की दो प्रमुख समस्याएं हैं—नदियों में हो रहे जल की निरंतर कमी और दूसरा गंदे नालों तथा औद्योगिक इकाइयों के और अपशिष्ट पदार्थों का नालों के माध्यम से इन नदियों पर मिलना। नमामि गंगे की घोषणा के बाद यह विश्वास बना था की गंगा की सफाई होगी और गंगा अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेगी किंतु इस दिशा में कोई ठोस कार्य न होने से दुखी गंगा पुत्र स्वामी सानंद ने गंगा की जीवन रक्षा हेतु आत्म बलिदान कर दिया किंतु उसका भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया।

नमामि गंगे योजना का लक्ष्य 2020 तक गंगा को निर्मल बनाकर उसे उसका मौलिक स्वरूप प्रदान करना रहा है किंतु अब तक की उपलब्धियों तथा कार्यों को देखते हुए उसे प्राप्त कर पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, उसका समय 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2016 में इसके लिए बने प्राधिकरण का विघटन कर नेशनल गंगा कौंसिल का गठन किया गया है किंतु निरंतर परिवर्तित हो रहे नामों से कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने देश की 351 नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है और नदियों की स्थिति को देखते हुए उसने उनकी निगरानी के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कुछ स्थानों को

छोड़कर गंगा का पानी पीने लायक तो दूर स्पर्श योग्य भी नहीं रह गया है नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का स्तर इतना बढ़ गया है कि वह मनुष्य की सेहत के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। नमामि गंगे योजना सफेद हाथी बनकर रह गई हैं जो सरकार द्वारा निर्गत भारी भरकम धनराशि को हजम कर जा रही हैं किंतु गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कोई सार्थक परिणाम प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव में इस दिशा में जो भी कार्य योजनाएं बनी उनको कभी अमल में नहीं लाया जा सका। उन्नाव के औद्योगिक इकाइयों से आने वाला कचरा कानपुर के गंदगी के साथ मिलकर गंगा में निरंतर आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है।

कानपुर सीमा से बांगरमऊ सफीपुर आदि अनेक कस्बों तथा उनसे छोटे 34 गांव का सीवेज और गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। प्रयागराज में भी गंगा की स्थिति इससे अलग नहीं है प्रयागराज में 82 नाले हैं जिनमें से अब तक मात्र 42 नाले ही टेप हो सके हैं। बिना टेप हुए 40 नालों का गंदा पानी वर्ष में मात्र 2 माह ही शोधित हो रहा, जबकि शेष 10 महीने प्रतिदिन इनका 13.8 करोड़ लीटर अपशिष्ट गंगा और यमुना में गिर रहा है। राजापुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की औसत क्षमता 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन है लेकिन यहां रोजाना 8 करोड़ लीटर नाले का पानी आता है जो शोधित करके गंगा में छोड़ा जाता है। इसी एसटीपी के बगल में राजापुर का नाला बहता है, जिससे ढाई करोड़ लीटर प्रतिदिन गंदा पानी सीधे गंगा नदी में चला जाता है।

नगरीय क्षेत्र में 40 छोटे बड़े नाले ऐसे हैं जिसके पानी का शोधन साल में सिर्फ 60 दिन हो पाता है अन्य दिनों में गंगा-यमुना में बिना शोधित हुए ही पानी प्रवाहित होता रहता है। स्पष्ट है

कि कागजों में भले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रयागराज आदि शहरों के नालों का गंदा पानी तथा उसका जहर गंगा में जाने से रोक दिया गया हो, व्यवहार में वह अब भी निरंतर गंगा में अपना जहर युक्त गंदा पानी डाल रहे हैं। कमोबेश यह स्थिति गंगा के समग्र प्रवाह पथ की है उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक गंगा में सफाई का कार्य एवं उसको प्रदूषण मुक्त किए जाने का कार्य बमुश्किल कहीं दिखाई पड़ता है किंतु उसको प्रदूषण युक्त करने तथा उसमें जहर घोलने का कार्य करने वाले अनेकानेक गंदे नाले अपनी पूरी क्षमता के साथ गंगा से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं।

वस्तुतः नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा या अन्य नदियों प्रदूषण मुक्त करने में जितना योगदान उन्हें गिरने वाले गंदे नालों को रोकने का है उससे बड़ा योगदान नदियों के जल स्तर को बढ़ाने से हो सकता है। यदि गंदे नालों को रोक दिया जाए और नदियों में बहने वाले जल के स्तर को बढ़ा दिया जाए तो इस समस्या का समाधान शीघ्र प्राप्त हो सकता है। जनमानस की सहभागिता के आधार पर ही किए गए कार्यों से नदियों की साफ सफाई हो सकती है किंतु अभी तक कहीं भी जनमानस का सहयोग दिखाई नहीं दे रहा। परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणाम भी कही परिलक्षित नहीं हो रहा है। दुनिया भर में नदियों को गतिशील बनाए रखने के लिए इसके तल से ड्रेजिंग व डेसिल्टिंग के माध्यम से उसकी गोद में विद्यमान गाद निकालने की निरंतर व्यवस्था की जाती है जिससे उनमें जल संचयन और जल प्रवाह में गति उत्पन्न होती है बिना नदियों को गति दिए उनको हम बचा नहीं सकते। जल संवर्धन एवं जल संरक्षण ही नदियों के जलस्तर में वृद्धि कर उन्हें गति दे सकता है जो आम जनमानस के सहयोग से ही संभव है। □□

पिछले 20 वर्षों में चीन ने डिजिटल तकनीकी आधार तेजी से विकसित कर लिया। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन ने डिजिटल तकनीकी कौशल में दक्ष कार्मिकों का ऑनलाईन नेटवर्क तैयार कर दिया और तकनीकी आधार पर मैन्युफैक्चरिंग विकसित कर ली। चीन ने कट्टर साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधारा पर केन्द्रित आर्थिक नीतिगत सुधारों द्वारा सरकारी के साथ-साथ निजी निवेश को असीमित रूप से बढ़ाते हुए उद्योग के सभी क्षेत्रों में तकनीकी विकास बढ़ा लिया। इस तरह विश्व में सबसे सस्ती दरों में उपलब्ध होने से चीनी उत्पादों की माँग सभी देशों में बढ़ गई, चीन का निर्यात अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के कारण चीन आज विश्व की सबसे ज्यादा विकसित एवं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

दूसरी ओर अमेजन और पिलपकार्ट जैसी कंपनियाँ डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर ऑनलाईन मार्केटिंग से त्वरित ग्राहक सेवा प्रदान करके विश्व व्यापार के विशाल करोबार पर एकाधिपत्य जमाने वाली सबसे बड़ी कंपनियाँ बन गई हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा आर्थिक विकास की तीव्र गति से 2030 तक चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक



— डॉ. रेखा भट्ट



अर्थव्यवस्था में 15.7 अरब डॉलर के संभावित योगदान के साथ संभावित वैश्विक विकास का लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होगा।

गार्टनर (विश्व व्यापार में शोध एवं परामर्श कंपनी) के अनुसार "वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत से अधिक वैश्विक कंपनियों के सीईओ की तकनीक में निवेश करना प्राथमिक आवश्यकता होगी" क्योंकि आज के डिजिटल युग में सस्ता विनिर्माण और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा व्यवसाय को सफल बनाने की पहली शर्त है। उत्पादों के खुदरा विक्रेताओं की निर्माण व उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये उपयोगी सामग्री व समय सीमा भी प्रमुख आवश्यकताओं में सम्मिलित है। पारंपरिक उद्योगों से हटकर आज कंपनियाँ दक्षता, उत्पादकता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार की तकनीकी सहजीविता के बगैर व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकेगी।

उद्योग एवं व्यापार के विनिर्माण (Manufacturing) उत्पादन एवं विपणन (Marketing) क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के हस्तान्तरण के लिये भारत आज जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हैं। भारत में निर्मित डिजिटल तकनीक आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण भारत में औद्योगिक और व्यवसायिक अस्थिरता ने देश में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है। वर्ष 2019 में औद्योगिक उत्पादन में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान देने वाले मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में गत वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत तक कमी आ गई है। आज भारत को वैश्विक व्यापार में ठोस स्थिति बनाने के लिये उत्पादों के विनिर्माण, विक्रय व विनिमय के लिये अपने ही देश में डिजिटल तकनीक का आधारभूत ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है तभी उद्यमिता में हम आत्मनिर्भर होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था सदृढ़ हो सकेगी।

आज चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में अमेरिका व्यापारिक घाटे की स्थिति से गुजर रहा है जिसमें अमेरिकावासियों के सुख सुविधापूर्ण जीवनशैली से अमेरिकी आयात कई गुना बढ़ गया है, वहीं चीन से लगातार सस्ते उत्पादों के आयात के कारण उसके उद्योग धंधे ठप्प हो जाने से निर्यात घट गया है।

केंद्र के स्किल इण्डिया कार्यक्रमों के तहत डिजिटल तकनीकी एवं कौशल में दक्ष युवा पीढ़ी के रूप में मानव संसाधन की भारत में असीम उपलब्धता है। विदेशों में उपलब्ध डिजिटल तकनीक की बुनियादी सुविधाओं की ओर आकृष्ट होकर यह युवाशक्ति विदेशी उद्यमों का आर्थिक विकास करके वहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती आ रही है। यह युवा पीढ़ी डिग्री प्राप्त कर बेरोजगारी की कतार में लगने की अपेक्षा अपने ही नेतृत्व में उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश के लिए उत्सुक है। आज कई भारतीय उद्यमी विश्व में प्रतिष्ठित स्टार्टअप के संस्थापक बन गये हैं और मात्र 5-6 वर्ष में पारम्परिक रूप से स्थापित व्यवसायों के मूल्यांकन की तुलना में कई गुना अधिक मूल्य के स्टार्टअप बन गये हैं। हारुन की मूल्यांकन सूची में भारत के सन् 2000 के बाद शुरू हुए स्टार्टअप आज चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर स्थापित हो चुके हैं।

एक सफल स्टार्टअप में उत्तम उपभोक्ता सेवा के लिये उच्च गति की डेटा संचरण सेवा (Connectivity) महत्वपूर्ण माध्यम होती है। 'डिजिटल

इण्डिया' कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट का विस्तार आज सुदूर गांवों तक फैल चुका है। भारत की 75 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। यदि ग्रामीण उत्पादकता स्त्रोतों को प्रौद्योगिकी विकास द्वारा तेजी से महानगरीय उद्योगों की तरह विकसित किया जाए तो भारत के गांवों का आर्थिक विकास होगा और ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा। तकनीकी संपन्न उद्योगों से स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा कम लागत में बने सस्ते उत्पाद उपलब्ध होने से ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ेगी।

कृषि प्रधान देश भारत में एफडीआई (Foreign Direct Investment) के अंतर्गत मोन्सेंटो जैसी विदेशी कंपनियों के दबाव में बीज तकनीक के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। जैसे महाराष्ट्र के किसानों को मोन्सेंटो ने जो आलू के बीज खरीदने पर मजबूर किया वे जीएम आधारित अत्यन्त विनाशकारक फसल उत्पादन का स्रोत है। भारतीय किसानों को प्रौद्योगिकीलब्धता के साथ सभी संसाधन उपलब्ध करवाये जायें तो कृषि उत्पादकता में उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस तरह भारत की मूल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से समूचे देश का आर्थिक विकास होगा।

आज चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में अमेरिका व्यापारिक घाटे की स्थिति से गुजर रहा है जिसमें अमेरिकावासियों के सुख सुविधापूर्ण जीवन शैली से अमेरिकी आयात कई गुना बढ़ गया है, वहीं चीन से लगातार सस्ते उत्पादों के आयात के कारण उसके उद्योग धंधे ठप्प हो जाने से निर्यात घट गया है। अमेरिका अपने आर्थिक हितों को साधने के लिये भारत में अमेरिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाने तथा RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) जैसे व्यापार

समझौते करने का दबाव बना रहा है।

केन्द्र की वर्तमान मोदी सरकार ने आरसीईपी समझौते से बाहर निकल कर सस्ते उत्पादों के विदेशी आयात को रोक दिया और अपने देश के किसानों, पशुपालकों, लघुउद्यमियों और व्यापारियों को होने वाले भारी नुकसान से बचा लिया है। अब केन्द्र सरकार के समक्ष बढ़ते वैश्वीकरण के साथ अपने देश के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती और देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक नीतिगत सुधारों के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट घोषणा में कॉरपरेट शुल्क में कमी, उद्योगों को भूमि अधिग्रहण और ऋण संबंधी नियमों को आसान बनाने संबंधी निर्णय लिये गये हैं जो न केवल विश्व बैंक के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत की स्थिति को अन्य देशों की तुलना में सुधारेंगे, बल्कि 'मेक इन इण्डिया' के स्थान पर 'मेड इन इण्डिया' की स्वदेशी अवधारणा को भी साकार करेंगे।

भारत में ऋग्वैदिक काल से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की भरपूर उपलब्धता के कारण उत्कृष्ट व्यापारिक अर्थव्यवस्था स्थापित रही है। कृषि की उत्पादकता तथा उद्यमिता द्वारा आय के पर्याप्त स्रोत रहे हैं। भारतीय उत्पादों की माँग भारत के अलावा विश्व

के सभी देशों में रहती थी। अतः भारत का व्यापारिक विस्तार सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त था। भारत में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग सभी प्रकार के व्यवसायों की प्रचुरता होने के कारण आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर युवाओं को राज्य से रोजगार प्रदान करने की माँग नहीं रहती थी।

19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया और भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के साथ राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी गुलाम बना लिया। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद के 70 वर्षों में डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के मुक्त व्यापार समझौते में सम्मिलित हो कर तथा एफडीआई के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति देकर भारत की तत्कालीन केन्द्र सरकार ने भारत को पुनः अमेरिका जैसे विकसित देशों की आर्थिक गुलामी की ओर धकेल दिया। यही कारण रहा कि भारत जैसे कृषि और पशुपालन की द्विआयामी अर्थव्यवस्था से संपन्न देश में आस्ट्रेलिया से सस्ते गेहूँ और चौथाई दर पर न्यूजीलैंड से दूध जैसे उत्पादों का आयात होता रहा।

औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों एवं कॉरपोरेट सेक्टर के निजी निवेश

के साथ-साथ सरकारी योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया निवेश, भारत के उद्यमिता क्षेत्र को मजबूत प्रौद्योगिकी आधार प्रदान करेगा। मुकेश अम्बानी जैसे स्थापित उद्योगपति के ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत बड़ा निवेश करने से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भारत के उद्योग जगत की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिलायन्स के चेयरमैन व एमडी मुकेश अम्बानी न्यूकॉमर्स के नाम से ई-कॉमर्स के रिटेल मार्केट में उतरेंगे। इस मार्केट का वर्तमान में 50 लाख करोड़ रूपए का टर्नओवर है जो 90 प्रतिशत असंगठित है। हाईस्पीड ऑनलाइन वितरण सेवा प्लेटफॉर्म से देश के 3 करोड़ व्यापारियों और किराना स्टोर को जोड़ा जायेगा, इससे 2028 तक देश का ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट 14.20 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा और रिलायंस कंपनी के अनुसार 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जायेगा।

भारत आर्थिक संकट से बाहर निकलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा तभी विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों में उद्यमियों, खुदरा व्यापारियों, कृषकों और सर्वहारा वर्ग के हित में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी और भारतीय वैभव की सनातन उद्यमशील परम्परा पुनः प्रतिष्ठित होगी। □□

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवेदना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

देर आए दुरुस्त आए नागरिकता संशोधन बिल पारित

देश विभाजन के तुरंत बाद किया जाने वाला बहु-प्रतीक्षित व प्राकृतिक न्याय वाला कार्य अब पूर्ण हुआ। संसद ने नागरिकता संशोधन बिल पारित कर दिया। चाणक्य ने कहा था कि ऋण, शत्रु और रोग को समय रहते ही समाप्त कर देना चाहिए। यदि राजनीति सही चली होती या रोगपूर्ण न होती तो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन न हुआ होता और आज नरेंद्र मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन बिल लाने की आवश्यकता न पड़ती। देश विभाजन के समय से लेकर आज तक हिंदुओं के साथ हो रहे सामाजिक, राजनैतिक अत्याचारों को रेखांकित करते हुये अमित शाह ने इस विधेयक के पारित होने के दौरान लोकसभा में कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23 फीसदी हिंदू थे लेकिन वहीं साल 2011 में ये आंकड़ा 1.4 प्रतिशत रह गया है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भारत मूकदर्शक नहीं बना रह सकता। जहां इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या चिंतनीय स्तर पर कम हुई है वहीं, भारत में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में असामान्य बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है।

बिल में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बहुप्रतीक्षित कानून के बाद घोषित रूप से इस्लामिक देशों में अत्याचार सह रहे हिंदुओं के भारत आने व यहां की वैध नागरिकता प्राप्त करने का स्वप्न साकार हो सकेगा। तथाकथित तौर पर कई राष्ट्रवादी नेताओं के मत की अनदेखी करके नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ जो समझौता किया था वह प्रारंभ से ही दरक गया था। वस्तुतः देश का विभाजन ही गलत वातावरण में किया गया था। गांधीजी कई कई बार बोलते थे कि “देश विभाजन मेरी लाश पर होगा”। उसी समय जिन्ना मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाते थे कि मुस्लिमों का पाकिस्तान बनकर रहेगा।

सर्वविदित है कि स्वतंत्रता के बाद जो हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में बच गए थे वे प्रताड़ित होते रहे व उनके संसाधन छीने गए, जबकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति व संख्या सुदृढ़ होती गई। वस्तुतः नागरिकता संशोधन विधेयक विलंब से लाया गया विधिक मार्ग है जिससे विभाजन

के समय के दीन-हीन हिंदुओं व अन्य समुदायों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नारकीय जीवन से बाहर निकलने का सम्मानपूर्ण मार्ग निकल सकेगा।

पाकिस्तान में मुस्लिमों के अत्याचारों से तंग होकर जो हिंदू बंधु भारत को अपनी भूमि समझकर यहां आकर रह रहे थे उन्हें अवैध माना जा रहा था व उन्हें नागरिक नहीं माना जा रहा था। हिंदू अपनी ही जन्मभूमि में पराया व अपमानित जीवन जीने को अभिशप्त था। इस अधिनियम के माध्यम से यह स्थिति समाप्त होगी। अब इस प्रकार के उपेक्षित हिंदू बंधुओं को भारत में सम्मान पूर्ण जीवन मिलेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में अत्याचारों से तंग होकर बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर चुके हिंदू अवैध अप्रवासी माने जाते थे। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। मोदी सरकार ने इस संवेदनशील विषय में अपने पहले कार्यकाल में कार्य प्रारंभ कर दिया था और 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को छूट दे दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून-1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 संसद में पेश किया गया था किंतु तब यह लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में विफल हो गया था व हिंदू चिंता का एक प्रमुख विषय कुत्सित व तुष्टिकरण राजनीति की भेंट चढ़ गया था। एनडीए सरकार के प्रयास से बिल दोनों सदनों से पारित होने पर देश में हर्ष की लहर है वहीं कांग्रेस सहित कुछ अन्य दल और संगठन मामले को न्यायालय में ले जाने की बात कर रहे हैं।

— स्वदेशी संवाद

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार संचालित उपक्रमों में विनिवेश का विरोध किया

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार संचालित उपक्रमों में विनिवेश के केंद्र के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि यह राष्ट्र के हितों के खिलाफ है तथा कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रभावित कुछ सलाहकारों तथा नौरकशाहों की मिलीभगत का परिणाम है। स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने हरिद्वार में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। एसजेएम ने कहा कि यह इस तरह के कदमों का विरोध करने का समय है। इसने कहा कि मोदी सरकार ने विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाभ में चलने वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री का निर्णय किया है। बीपीसीएल के विनिवेश का विरोध करते हुए एसजेएम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह निश्चित तौर पर अच्छा कारोबारी कदम नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की दूसरी सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी नियमित तौर पर लाभ अर्जित कर रही है। इसने कहा, “ऐसी खबरें हैं कि इन संपत्तियों पर सरुदी अरब की नजर है। यह सिर्फ अस्वीकार्य ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। संपत्ति राष्ट्रीय भावना से स्थापित की गई थी और इसे विदेशी तेल कंपनियों के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए।” एसजेएम ने एअर इंडिया और बीएसएनएल के विनिवेश का भी विरोध किया।

<https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/rss-linked-swadeshi-jagran-manch-opposed-disinvestment-in-government-run-enterprises/articleshow/72338430.cms>

देश की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी जागरण मंच का योगदान अतुलनीय



स्वदेशी जागरण मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निराला सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ‘स्वदेशी की संकल्पना एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी’ विषयक संगोष्ठी में जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक डा. वीके सिंह ने स्वदेशी के स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में

स्वदेशी जागरण मंच का योगदान अतुलनीय है।

प्रांत सह संयोजक ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, इसके बारे में जयंती वर्ष 2019-20 पर स्वदेशी जागरण मंच लोगों के बीच जाकर बताया जाएगा। संगोष्ठी में प्रयागराज क्षेत्र के संयोजक पंकज कुमार ने कहा कि जागरण मंच की स्थापना क्यों की गई, इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत के उद्योग, बौद्धिक संपदा, संस्कृति को संरक्षित कर रोजगार परक अर्थव्यवस्था स्थापित करना ही स्वदेशी और ठेंगड़ी जी का सपना था। कार्यक्रम में विभाग महिला प्रमुख आदर्श त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विभाग संघर्ष वाहिनी प्रमुख गंगेश नारायण, जय प्रकाश गुप्ता, डा. भावेश, अवनीश मोहन शर्मा, रंजना मिश्र, किरण उपाध्याय, वंदना शर्मा, लक्ष्मी उपाध्याय, रामदत्त मिश्र, अमरेंद्र, विवेक, विकास आदि मौजूद रहे।

<https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/swadeshi-jagran-manch-prayagraj-allahabad-news-ald2609208186>

आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच सबसे बड़ा संगठन



स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने कहा आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच सबसे बड़ा संगठन है। मंच की यात्रा 1991 से चल रही है। संघर्षों के बाद आज भी परिस्थितियां गंभीर हैं। विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर भारत को न चलने की वकालत करते हुए कहा भारत को विश्व का नेतृत्व करने के लिए काम करना चाहिए।

राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा प्रेमनगर आश्रम में चल रहे स्वदेशी जागरण मंच के तीन दिवसीय 14वीं राष्ट्रीय सभा के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कहा कार्यकर्ताओं के दम पर आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच सबसे बड़ा संगठन बना है। स्वदेशी जागरण मंच दो प्रमुख कार्य आर्थिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष और स्वदेशी भाव का जागरण कर रहा है। घर और परिवेश, चूल्हे चौके के बदलते स्वरूप के लिए विदेशी फूड कंपनियों को जिम्मेदार बताया। श्री अरुण ओझा 11 वर्ष से राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व निभाने के बाद विश्राम की इच्छा

जताई। इसके बाद डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा ने मदुरै निवासी श्री आर. सुंदरम, जो राष्ट्रीय सहसंयोजक थे, को राष्ट्रीय संयोजक बनाने की घोषणा की।

<https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-swadeshi-jagran-manch-19807199.html>

स्वदेशी अपनाने से बढ़ता है देश का गौरव: बेबी रानी मौर्य



हरद्वार के प्रेमनगर आश्रम में स्वदेशी जागरण मंच की तीन दिवसीय 14वीं राष्ट्रीय सभा के दूसरे सत्र की मुख्य अतिथि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश का गौरव बढ़ता है। स्वदेशी उत्पाद और विचार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कहा कि स्वदेशी जागरण मंच इस आयोजन के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगा रहा है।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिये स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह सराहनीय कार्य है। इससे स्थानीय कामगारों और श्रमिकों को स्वावलंबन का बल मिलता है। स्वदेशी उत्पाद स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा स्वदेशी से अपना देश, अपनी माटी का भाव जगता है। यदि हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे तो अपनी पहचान भूल जाएंगे। कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में जुटी हैं। यहां तक कि कैंसर के इलाज की जड़ी-बूटी भी उन्होंने खोजी है। राज्यपाल ने स्वदेशी जागरण मंच व स्मृति विकास संस्थान की ओर से आयोजित स्वदेशी उत्पादों की 50 स्टॉलों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इसे सराहा। स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला प्रमुख अमिता ने राज्यपाल को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

<https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-national-swadeshi-conference-in-haridwar-19800697.html>

इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी)-2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (सेकेंड अमेंडमेंट) विधेयक-2019 के जरिये संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इस विधेयक के जरिये इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया में हो रही कुछ दिक्कतों को दूर करना चाहती है और कारोबारी सहूलियत को बढ़ावा देना चाहती है। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। बयान के मुताबिक यह विधेयक आईबीसी-2016 की धारा 5(12), 5(15), 7, 11, 14, 16(1), 21(2), 23(1), 29ए, 227, 239, 240 में संशोधन करेगा और इसमें एक नई धारा 32ए जोड़ेगा।

<https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-bill-approved-for-amendment-of-insolvency-and-bankruptcy-code-126264898.html>

उपहार के तौर पर चीन से हो रहे आयात पर रोक

चीनी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जा रही टैक्स की चोरी के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच की मुहिम रंग लाई। भारत सरकार ने उपहार के रूप में आयात किये गये सामानों को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि कूरियर और डाक विभाग के माध्यम से उपहार के तौर पर मंगाये जाने वाले सामानों पर भी अब नियम के मुताबिक शुल्क देना होगा।

मालूम हो कि चीनी ई-कॉमर्स कंपनियां लंबे समय से टैक्स की चोरी कर रही थी। चीनी पोर्टल के जरिये उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये सामान को उपहार के तौर पर कूरियर या डाक से भेजती थी। ऐसे सामानों पर प्रचलित कर नहीं वसूल किये जाते थे। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता था। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता इस तरह की ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जा रही हेराफेरी के खिलाफ समय-समय पर गंभीरता आवाज उठाते रहे हैं। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि जीवन रक्षक दवाइयों तथा

रक्षाबंधन के अवसर पर भेजी जाने वाली राखी के अलावा हर तरह के उपहार पर प्रतिबंध रहेगा। अब भविष्य में प्रचलित करों का भुगतान कर ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपहार के रूप में आने वाला सामान भी आ सकेगा।

इरडा ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ में निवेश की अनुमति दी

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश की अनुमति दे दी। बीमा नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऋण ईटीएफ को निवेश के लिये उपयुक्त माना है। इरडा ने एक परिपत्र में कहा कि नियामक केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध बांड ईटीएफ में निवेश की अनुमति देता है। परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के बांड ईटीएफ सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड द्वारा जारी होना चाहिए और उसके नियमन से संचालित हो।

<https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/irda-allows-insurance-companies-to-invest-in-debt-etfs-of-central-psus/articleshow/72480267.cms>

सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती के बावजूद निर्यात में पीछे है देश



दुनिया में सर्वाधिक ऑर्गेनिक खेती का रकबा होने के बावजूद वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। कृषि क्षेत्र के इन परस्पर विरोधी आंकड़ों पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताते हुए इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोन और ई-ऑर्गेनिक बाजार स्थापित करने का सुझाव दिया है। कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में ऑर्गेनिक उपज का निर्यात सबसे मुफीद साबित होगा।

समिति ने राज्यसभा में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने रासायनिक खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को भी मुहैया कराने का सुझाव दिया है, ताकि उनकी लागत घट सके। समिति ने कहा है कि पूर्वोत्तर

के राज्यों के साथ पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। समिति ने ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजार में ब्रांड वैल्यू स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया है।

ऑर्गेनिक (जैविक) खेती के की उपज के मामले में भारत दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश है। यहां सर्वाधिक लघु व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए इस तरह की खेती काफी लाभप्रद हो सकती है। लेकिन वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की सर्वाधिक मांग है, जिसके मद्देनजर इस तरह की खेती पर जोर देने की जरूरत है।

राज्यसभा सदस्य वी. विजयदेसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय स्थायी संसदीय समिति ने 'एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रु चौलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज' विषय पर अपनी सिफारिशें सदन में प्रस्तुत कीं। इस विषय पर समिति ने लगभग सवा साल में कुल सात बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने कॉमर्स, कृषि व किसान कल्याण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, राज्य सरकारें, जैविक किसान संगठनों और एजेंसियों के साथ रिसर्च, ट्रेड और निर्यात संगठनों से लंबी चर्चा की है। समिति ने देश के पहले ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम का दौरा भी किया। समिति ने जैविक खेती की चुनौतियों को चिन्हित किया है। इनमें छोटी जोत, अधिक लागत, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड व अन्य बायो खाद का महंगा होना और उपज के लिए उचित बाजार न होना प्रमुख हैं। उपज के लिए सर्टिफिकेट मिलना बहुत महंगा होने के साथ नीतिगत समर्थन का न मिलना जैविक खेती की राह के रोड़े हैं। समिति ने पाया कि विश्व बाजार में जैविक उत्पादों की जबर्दस्त मांग है, जिसके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोन (ओपीजेड) बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जैविक उत्पाद के लिए उचित बाजार मुहैया कराने की दिशा में तत्काल ई-बाजार स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को उपभोक्ता से सीधे जोड़ने में मदद मिलेगी। समिति ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जैविक खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

<https://www.jagran.com/business/biz-despite-the-highest-organic-farming-area-the-country-is-lagging-in-exports-19837685.html>

डिजिटल में अमेरिका और चीन को पछाड़ सकता है भारत: रिपोर्ट

साल 2030 तक भारत एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। डिजिटल की रेस में भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों से आगे निकल सकता है। आगामी वर्ष में अमेरिका की अमेजन और चीन की टेंसेंट जैसी भारत में आठ कंपनियां



हो सकती हैं। अमेरिका की जीवीजी कैपिटल ने एक 'कौन जीतेगा अगली डिजिटल रेस' नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हेल्थ, फूड, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम जैसे बड़े क्षेत्रों में तेजी से विकास हो सकता है। भारत की एयरटेल, डीमार्ट, गोदरेज और रिलायंस जैसी अन्य कंपनियां काफी मजबूत हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली डिजिटल रेस यानी साल 1995 से अबतक दुनिया में आठ डिजिटल दिग्गज कंपनियां आई हैं, जिनमें से छह कंपनियां अमेरिका की हैं। इनमें अमेजन, एपल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स शामिल हैं। वहीं अलीबाबा और टेंसेंट चीन की कंपनियां हैं। साथ ही दुनिया की 10 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनियों में से सात कंपनियां इन्हीं में से हैं। वहीं दूसरी डिजिटल रेस यानी 2020 से 2030 में भारत जैसे 15 देशों से लगभग 40 नए डिजिटल दिग्गज पैदा होने की संभावना है। उभरती बड़ी कंपनियों के पास बढ़ोतरी का ज्यादा मौका है।

बता दें कि अमेरिका की जीवीजी कैपिटल द्वारा जारी की गई 'कौन जीतेगा अगली डिजिटल रेस' रिपोर्ट 100 देशों की 5000 कंपनियों की स्टडी के आधार पर तैयार की गई है।

<https://www.amarujala.com/business/business-diary/india-predicted-to-beat-us-china-in-next-digital-race-according-to-gvg>

मानव विकास सूचकांक: भारत एक पायदान ऊपर

मानव विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन से भारत एक पायदान ऊपर 130 से 129 पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2005-06 से 2015-16 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। यूएनडीपी की भारत स्थित प्रतिनिधि शोको नोडा ने बताया, 189 देशों की सूची में पाकिस्तान तीन पायदान की छलांग लगाते हुए 150 से 147वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश दो पायदान ऊपर पहुंच कर 134वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भारत पिछले साल इस सूची में 130वें पायदान पर था। उसका मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.647 है, जबकि दक्षिण एशिया का 0.642 है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन दशकों में तेजी से विकास के

कारण गरीबी में कमी आई है। इसके साथ ही जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिक्षा और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सेवा तक आम जनता की पहुंच के कारण रैंकिंग में यह सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 1990 से 2018 के दौरान दक्षिण एशिया में 46 फीसदी विकास हुआ। उसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43 फीसदी विकास हुआ।

मानव विकास सूचकांक में शीर्ष 10 देश: 1. नॉर्वे, 2. स्विट्जरलैंड, 3. ऑस्ट्रेलिया, 4. आयरलैंड, 5. जर्मनी, 6. आइसलैंड, 7. हॉन्गकॉन्ग, 8. स्वीडन, 9. सिंगापुर, 10. नीदरलैंड।

<https://www.amarujala.com/business/business-diary/human-quality-index-india-notches-up-by-one-step-reaches-at-129-position>

स्वदेशी जागरण मंच ने मेड बाय इंडिया पर दिया जोर



स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा बड़ौत के वैदिक मॉडर्न कॉलेज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता श्री कमलजीत (अ.भा. सहसंपर्क प्रमुख) ने कहा कि स्वदेशी हमें मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का नवाचार के माध्यम से समाधान करते हुए नए रोजगार खड़े करना, यह स्वदेशी स्टार्ट-अप का एक कार्य है। युवा पीढ़ी में स्वयं अभिमान अनाए रखने के लिए उद्यमिता विकास की भावना पैदारा करने की आवश्यकता है। हम रोजगार देने वाले बनें, मांगने वाले नहीं। प.उ.प्र. प्रांत संयोजक श्री अनिल लुहारी ने स्वदेशी की अवधारणा व स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा विगत 28 वर्षों में प्रमुख कार्यों व आंदोलनों के रूप में कार्य कर रहा है व आज स्वदेशी समय की आवश्यकता है।

स्वदेशी जागरण मंच इस वर्ष मुख्य रूप से परिवार, पर्यावरण व रोजगार विषय पर कार्य करेगा तथा राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्मशताब्दी वर्ष भी प्रमुखता से मनाया जायेगा। इस गोष्ठी में डॉ. देवेंद्र सोलंकी, डॉ. अमित राणा ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर चौ. राजवीर सिंह, रेनू आर्य, संजीव तालियान, डॉ. शशिकांत शर्मा, सुनील, जयवीर, विकास शर्मा, उदयवीर, कपिल, अमरदीप, संदीप बड़ौली, अरविंद कुमार, विक्रान्त, प्रशांत, परमजीत आदि उपस्थित रहे।



<https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-made-in-india-19830608.html>

विकास तो हो नहीं रहा, विनाश दिख रहा है: डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण हेतु स्वदेशी जागरण मंच की ओर से पीपुल्स गंगा एक्ट 2019 का मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। विषय के जानकार लोगों की राय से तैयार किये गये दस्तावेज में गंगा की अविरल धारा, गंगत्व से युक्त निर्मल धारा, हिमालय में विनाश-आपदा को नियंत्रित करने के सुझावों के साथ-साथ संस्कृति के बाजारीकरण को रोकने की भी मांग शामिल है। सरकार से मांग की गई है कि समूची मानवता को एकसूत्र में पिरोने वाली विश्व धरोहर गंगा नदी के गंगत्व को संजोकर हमें उसी रूप में अगली पीढ़ी को देना चाहिए, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है।

नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाना अब एक घाटे का सौदा तो हो ही गया है, जीवनदायिनी नदियों के लिए भी बड़ा संकट बनकर उभरा है। त्रिपथगा, प्राणदायिनी गंगा का अस्तित्व खतरे में है। विकास के नाम पर चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों के अंधाधुंध तोड़फोड़ के बाद अब चार धाम यात्रा के बहाने सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पहाड़ों का सीना चीरकर मां गंगा के स्वरूप को खत्म करने की कोशिश चल रही है। पर्यावरण प्रेमियों को प्रकृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा तथा तर्कों के साथ सरकार के संतुलनकारों को यह बताना होगा कि जब दुनिया भर के विकसित देश बांधों से पिंड छुड़ा रहे हैं, तो भारत अपनी महान विरासत नदियों की कीमत पर बांध बांधने पर आमादा क्यों हैं?

अविरलता, निर्मलता तथा गंगत्व को बचाये रखने की गरज से दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि पर्यावरण की लड़ाई स्वदेशी की लड़ाई है। स्वदेशी जागरण मंच प्रारंभ से ही प्रकृति के अनुपम उपहारों मसलन नदियों, पहाड़ों, झरनों, वनों आदि की रक्षा-सुरक्षा के लिए तत्पर रहा है।

मालूम हो कि राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण हेतु संसद में एक बिल लाया जाना प्रस्तावित है। डॉ. महाजन ने कहा कि अच्छा होता कि सरकार बिल लाने के पहले स्वदेशी जागरण मंच द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज को संज्ञान में ले तथा इसी के अनुरूप बिल प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि नदी मामलों के मंत्री तथा अधिकारीगण एकसाथ बैठकर सर्वसम्मति से गंगा सहित देश भर की नदियों को बचाने के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें जो सिर्फ कागजी न हो बल्कि उसे जमीन पर भी उतारा जा सके।

अपनी बात रखते हुए डॉ. महाजन ने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है। भारत मूलतः एक भोगवादी देश नहीं है। बिजली की जरूरत देश में है लेकिन जितनी जरूरत है उससे अधिक बिजली हम उत्पादित करने की स्थिति में है। उन्होंने बताया कि बांध बनाकर तैयार की गई बिजली अन्य माध्यमों से तैयार की जाने वाली बिजली से कई गुणा महंगी भी है। वहीं कुछ साल के बाद करोंडों, अरबों के खर्च से तैयार किये जाने वाले बांध सरकार पर लाईबिलिटी की तरह हैं। आंकड़ों सहित उन्होंने बताया कि आज देश में 2.65 रु. प्रति यूनिट की दर से सोलर क्षेत्र की कंपनियां बिजली बेचने के लिए घर-घर अर्जी लगा रही है। ऐसे में लगभग 7 रु. प्रति यूनिट की दर से तैयार किये जाने वाले हाइड्रो पावर की बिजली बनाने का औचित्य क्या है?

गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े हेमंत और मल्लिका ने गोष्ठी के दौरान गंगापुत्र जी.डी. अग्रवाल के बलिदान पर प्रकाश डाला तथा प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज प्रोजेक्टर के जरिये लोगों को दिखाया। इस दौरान अपनी राय रखते हुए के.एन. गोविन्दाचार्य ने कहा कि हमें गंगा के महत्व को प्रमुखता के साथ लोगों के बीच ले जाना चाहिए तथा आमजन को जोड़कर इस अभियान को गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टाम्टा ने कहा कि गंगा पर अब तक जितने भी कार्य हुए उसका परिणाम सार्थक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब तक आम आदमी इस अभियान में नहीं जुड़ता सरकारें भी दृढ़ ईच्छाशक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ेगी।

इस क्रम में अपनी बात रखते हुए समाजवादी नेता सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने कहा कि सरकारें बांध बनाकर बिजली देने और सिंचाई सुविधा देने का लॉलीपॉप देती रही है। आजादी के बाद बने पहले बांध पर पंडित नेहरू ने कहा था कि इससे उत्तर भारत का क्षेत्र सिंचित हो जायेगा तथा एक हजार मेगावाट बिजली मिलेगी। यह सपना, सपना ही रह गया। पूर्व सांसद डॉ. कर्ण सिंह ने गंगा संरक्षण अभियान में सहयोग देने का आश्वासन दिया और लगे हाथों यह भी नसीहत दी कि बिना सत्ता शासन के सहयोग के यह संभव नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख दीपक शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन को स्पष्ट करते हुए गंगा संरक्षण की बात की जानी चाहिए। संगोष्ठी में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। □□

स्वदेशी गतिविधियाँ

श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी

जन्मशताब्दी वर्ष (2019-20)

सचित्र झलकियां



जोधपुर, राजस्थान



जोधपुर, राजस्थान



दिल्ली (केंद्रीय कार्यालय)



कुल्लू, हिमाचल प्रदेश



प्रयागराज



पंजाब



पश्चिमी विभाग, दिल्ली

चित्तौड़ प्रांत सम्मेलन (राजस्थान)



स्वदेशी गतिविधियां

14वीं राष्ट्रीय सभा

हरद्वार (उत्तराखण्ड)

29, 30 नवंबर व 1 दिसंबर 2019

सचित्र झलकियां



प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती